साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 15 सितंबर से 21 सितंबर 2025
हम दिखाएंगे आईना...
वर्ष : 01 अंक : 28 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 03 में...
मेट्रो के लिए फिर डीपीआर

पेज 12 में...
नशे के बाद नंगापन

पेज 11 **राज्योत्सव में आसमान से बरसेंगे फूल**

शेम...शेम
क्या मैच जरुरी है

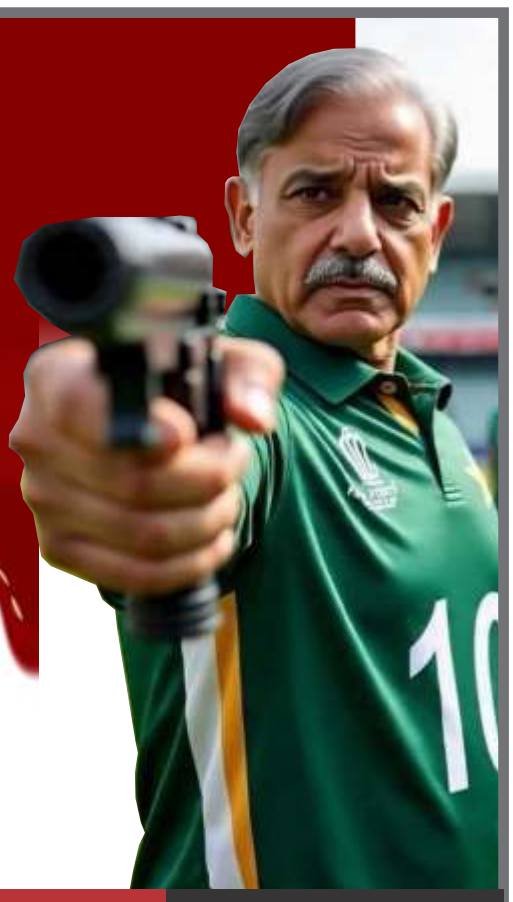

हार तो दूर ऐसी टीम से जीत भी देश को मंजूर नहीं

इस मैच से भिखारिस्तान की जेब में जाएंगे 116 करोड़	पहले ऑपरेशन सिंदूर, अब आतंकिस्तान के साथ खेल	क्या सरकार से ज्यादा ताकतवर है बीसीसीआई, आईसीसी	टेरर और टॉक के बाद खून और पानी का डायलॉग क्यों भूले	पहलगाम पीड़ित बोले- जिनके हाथ खून से सने, उन्हीं से मैच	देशभर में मुखर विरोध, सोशल मिडिया में तंज, मीम वायरल

(शहरसत्ता टीम) पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच खेले जाने पर 53 फीसदी हिन्दुस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से ब्रॉडकास्टर्स मुनाफ़ा कमाएंगे, आईसीसी और एसीसी रेवेन्यू बांटेंगे, और दुनिया भर के लाखों फैंस इसे देखेंगे. हालांकि, घर पर जश्न का माहौल फीका रहेगा. पहलगाम में अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए, सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए, और खेल के औचित्य पर सवाल उठाने वाले आम नागरिकों के लिए, यह सिर्फ़ क्रिकेट नहीं है.जाहिर है विपक्ष भी सरकार के इस फैसले से खफा भी है और सियासी दस्तूर के तहत जनभावना के साथ है। यह समझ से परे है कि आखिर पहलगाम, उरी, पुलवामा के बाद भारत सरकार के एक्शन से पीड़ित परिवार ही नहीं पूरे देश का दिल जितने वाली केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप के लिए आतंकिस्तान के साथ मैच खेलने की अनुमति क्यों दी। ऐसी क्या मज़बूरी थी कि सरकार से ज्यादा ताकतवर बीसीसीआई, एसीसी और आईसीसी साबित हुई। टेरर और टॉक के बाद खून और पानी का डायलॉग क्यों और कैसे भूल गया देश ?

पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच खेले जाने पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दलों से लेकर शहीद परिवारों तक सबने सरकार और बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा किया है। देश का गुस्सा, मैच की मजबूरी और सरकार पर जान से ज्यादा मैच आखिर क्यों ज़रूरी हो गया यह सभी जानना चाहते हैं।

भाजपा नेता और सरकार के मंत्री दलील दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुकाबले नहीं खेलेगा, न तो भारत को कोई खिलाड़ी पाकिस्तान जाएगा और न ही पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। लेकिन बहुपक्षीय मुकाबले खेले जाएंगे। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर सरकार ने साफ किया है कि 'खेल और ऑपरेशन सिंदूर' दो अलग-अलग मुद्दे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा किजोर देकर कहा कि मैच को आयोजित करने के फैसला 'सोच-समझकर' लिया गया है, क्रिकेट की अपनी भावनाएं हैं जो राजनीति से परे हैं। इसके उलट कांग्रेस, आप पार्टी और शिवसेना समेत अससुद्दीन ओवैसी भी इस अप्रत्याशित खेल भावना को लेकर सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं।

मैच को लेकर दो धड़ों में बंटे फैंस

भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर फैंस दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं होचा चाहिए, चाहे वो खेल हो, व्यापार हो, या पीनी। वहीं दूसरा धड़ा कह रहा है कि खेल को खेल ही रहने दिया है, इसे राजनीति से न जोड़ा जाए। जिस तरह सेना के पाकिस्तान हमेशा बॉर्डर पर धूल चटाई है, उसी तरह खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैदान पर धूच चटाएंगे।

मज़बूरी या जरुरी ?

अगर वीज़ा रद्द किए जा सकते हैं, अगर लोगों के बीच आपसी संबंध ख़त्म किए जा सकते हैं, अगर जल संधियां भी रोकी जा सकती हैं, तो सिर्फ़ क्रिकेट के साथ ही अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? क्या इसकी वजह आर्थिक दांव पर बहुत ज़्यादा है, या फिर इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय भावना से ऊपर रखा गया है? क्या वैश्विक खेल आयोजनों की मेज़बानी राष्ट्रीय हित से ज़्यादा अहम है? और अगर आईसीसी टूर्नामेंटों के मैचों का बायकॉट करने से अलगाव का ख़तरा है, तो क्या यह देश की अंतरात्मा पर भारी पड़ता है?

हम करते हैं मैच का बहिष्कार

शहर सत्ता अख़बार ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा और पहलगाम समेत अब तक आतंकिस्तान द्वारा किये गए हमलों में शहीद हर उस भारतीय परिवार और जनभावना के साथ है जो दुश्मन देश को नेस्तनाबूद होते देखना चाहते हैं। इसके मद्देनजर शहर सत्ता परिवार भारत-भिखारिस्तान के बीच होने वाले बेवजह और बेमानी एशिया कप की कवरेज भी नहीं करेगा। हम टेरर और टॉक के साथ ही खून और पानी बहाने वालों का मुखर विरोध करते हैं। बीसीसीआई, आईसीसी, असीसी के भारत-आतंकिस्तान मैच का बहिष्कार करते हुए मैच की ख़बरें और कवरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसी खेल भावना और मज़बूरी से हम नहीं बांधें है इसलिए दोनों देशों के इस आयोजन को और भविष्य के सभी खेलों की ख़बरें नहीं प्रसारित करेंगे।

-संपादक शहर सत्ता

साप्ताहिक शहर सत्ता

खून की होली खेलने वालों के साथ "खेल"

जवाब सीधा है- पैसा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) जानती हैं कि भारत-पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं बिकता. टेलीविजन दर्शकों की संख्या बढ़ती है, विज्ञापन स्लॉट प्रीमियम रेट पर बिकते हैं, और प्रायोजकों की लाइन लग जाती है।

साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में, उनके मुकाबले को भारतीय टेलीविजन पर 26 अरब मिनट का चौंका देने वाला समय मिला, जो 2023 में होने वाले विश्व कप मुकाबले से भी ज़्यादा है. क्रिकेट बोर्डों के लिए, ये आंकड़े बेहद अहम हैं. सिर्फ़ तीन आईसीसी टूर्नामेंटों के मीडिया अधिकारों की कीमत करीब 1,400 करोड़ रुपये है, जिसमें हर सदस्य देश को सैकड़ों करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलना तय है, जो भारत के बिना अकल्पनीय है, और भारत-पाकिस्तान मैच के बिना तो बिल्कुल भी नहीं।

जान से ज्यादा मैच ज़रूरी?

असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM प्रमुख) ने कहा कि यह सरकार की दोहरी नीति है।"एक ओर ये पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं, दूसरी ओर वहीं से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसों की कमाई क्या शहीदों की शहादत से बड़ी हो गई?"

उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT प्रमुख) ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जब तक पाकिस्तान की जमीन से आतंक का खेल जारी है, तब तक भारत को उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। चाहे वह खेल हो या कारोबार।"

शरद पवार (NCP प्रमुख) ने संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है। "लोगों की भावनाएँ अलग हैं, लेकिन यह फैसला सरकार और क्रिकेट बोर्ड की ओर से लिया गया है। मैच को लेकर दबाव भी होता है।"

कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मुनाफे और राजनीति को प्राथमिकता दी और शहीदों की भावनाओं को दरकिनार कर दिया।

अशोक पंडित (फिल्म निर्देशक एवं IFTDA प्रमुख) ने इसे "देश के लिए काला दिन" करार दिया और कहा कि आयोजकों में संवेदनशीलता की कमी है।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश का बहिष्कार करने से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। यह सब जानते हुए भी खेल जारी रखना कितनी शर्म की बात है। हम देख रहे हैं कि भाजपा ने अपनी विचारधारा और देशभक्ति की परिभाषा बदल दी है।

पूर्व CM अरविंद केजरीवाल - क्लब, पब और रेस्टोरेंट्स मैच न दिखाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे। यह देश के साथ धोखा है।

सांसद संजय राऊत- देशभक्त नागरिकों को सोशल मीडिया पर उन रेस्टोरेंट और क्लबों की जानकारी शेयर करनी चाहिए जहां भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच दिखाया जाएगा।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जिस देश के साथ हमारा विवाद चल रहा हो, उसके साथ क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है। इस मैच से अमित शाह के बेटे जय शाह और BCCI पैसा कमा रहा है।

AIMIM दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने X में लिखा- दिल्ली में आज भारत-पाक मैच का कोई भी पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। पहलगाम के शहीदों का मजाक बनाने के लिए बीजेपी शर्म करे।

आप सांसद संजय सिंह ने कहा- जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, तो फिर क्रिकेट कैसे खेला जा रहा है? क्या देश की इज्जत से ज्यादा पैसा अहम है?

पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा कि यह विषय बोलने लायक नहीं है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। जब हमारे लोगों का खून बहा है, तो फिर उनसे खेल का क्या मतलब?

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की नीति अपनाता है और आतंकियों को पनाह देता है। इस वजह से पाकिस्तान से किसी तरह का खेल, सांस्कृतिक या कूटनीतिक संबंध नहीं होना चाहिए।

शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में हिंदू होने पर लोगों को गोली मारी गई और 26 महिलाएं विधवा हुईं। सावंत ने सवाल किया- क्या हम शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी के दर्द को देखकर भी पाकिस्तान से मैच खेलेंगे?

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि मैच होना चाहिए। बायलेटरल सीरीज में नहीं खेलेगी, इसलिए अभी हम कहें, आप कहें या जो भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लेयर्स और बीसीसीआई को वही मानना पड़ेगा जो सरकार कह रही है।

रायपुर मेट्रो के लिए फिर से डीपीआर बनाने की कवायद शुरू

रिपोर्ट यह बताएगी कि मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चले, कहां स्टेशन बने

- नए सिरे से होगा टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अध्ययन, एजेंसी चयन के लिए आरएफपी जारी
- मेट्रो कॉरिडोर छत्तीसगढ़ को आधुनिक शहरी ढांचे से जोड़ देगी

रायपुर। रायपुर मेट्रो का सपना एक दशक से अधिक समय से फाइलों में दफन है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नवा रायपुर से राजनांदगांव तक का डीपीआर तैयार किया था, लेकिन अदूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हुई है। सरकार ने टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए एजेंसी चयन हेतु टेंडर जारी कर दिया है। रिपोर्ट के आधार पर नया डीपीआर तैयार होगा और तय होगा कि मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी और किन जगहों पर स्टेशन बनेंगे। राजधानी क्षेत्र में नई कनेक्टिविटी की तैयारी- नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के रूप में विकसित करने की योजना है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यह क्षेत्र एकीकृत महानगरीय परिवहन नेटवर्क से जुड़ सके, इसके लिए मेट्रो ट्रेन को आधार स्तंभ माना गया है। सरकार का दावा है कि यह केवल परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का नया इंजन साबित होगी। मौजूदा आधारभूत ढांचा नवा रायपुर अटल नगर पहले से ही स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में तैयार है। यहां बीआरटीएस कॉरिडोर, मल्टी-मॉडल स्टेशन, इलेट्रिरक रिक्शा सेवा और हाईवे नेटवर्क मौजूद हैं।

दीर्घकालिक लक्ष्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। मेट्रो कॉरिडोर इस दिशा में अहम कदम साबित होगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से अविकसित क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए अनुकूल ढांचा तैयार होगा और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

सरकारी पहल, बजटीय प्रावधान

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मेट्रो परियोजना के टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जुलाई से अध्ययन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीआरडीए) गठित किया गया है, जिसमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। हाल ही में विधानसभा ने छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 भी पारित किया है, जिससे योजनाबद्ध विकास को संस्थागत ढांचा मिल गया है।

2031 तक 50 लाख आबादी को ध्यान में रखकर प्लान

विशेषज्ञ मानते हैं कि 2031 तक रायपुर दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर में 50 लाख से अधिक आबादी होगी। बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के चलते रायपुर दुर्ग-भिलाई, इन तीनों शहरों में ट्रैफिक जाम पहले से ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में मेट्रो ट्रेन सिस्टम को अनिवार्य विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मेट्रो परियोजना से केवल परिवहन नहीं, बल्कि नई औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को गति मिलेगी। नए व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे, संपत्ति की कीमतें बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

राज्य स्थापना दिवस से नई पुलिसिंग प्रणाली लागू करने की तैयारी

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी अब निर्णायक मोड़ पर

रायपुर। राजधानी रायपुर में लंबे समय से चल रही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। शासन ने इसके लिए एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें तीन आईजी, एक डीआईजी, एक एसपी और संयुक्त संचालक लोक अभियोजन अधिकारी भी शामिल हैं। यह कमेटी अगले डेढ़ महीने में अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

चर्चा यह भी है कि यदि रिपोर्ट समय पर नहीं आई, तब भी राज्य स्थापना दिवस एक नवंबर से रायपुर में कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत कर दी जाएगी। शुरुआती दौर में आईजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर (सीपी) की जिम्मेदारी देकर व्यवस्था का खाका तैयार किया जाएगा।

आईजी स्तर के अधिकारी पर नजर

शासन को भेजे गए प्रस्ताव में पुलिस कमिश्नर पद पर एडीजी या आईजी रैंक के अधिकारी को पदस्थ करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में आईजी स्तर के किसी अधिकारी को सीपी बनाकर व्यवस्था में कसावट लाने पर जोर है। इस स्थिति में वर्तमान एसएसपी को जॉइंट कमिश्नर का पद देकर उनके मौजूदा अमले के साथ काम शुरू किया जा सकता है। इस समय आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा, आईजी बिलासपुर संजीव शुक्ला और आईजी पीएचक्यू बद्रीनारायण मीणा का नाम इस पद के लिए चर्चा में है। रायपुर ग्रामीण के लिए अलग एसपी राजधानी में वर्तमान में 32 थाने हैं। सूत्र बताते हैं कि इनमें से लगभग आठ आउटर थानों को अलग कर एक नया रायपुर ग्रामीण जिला बनाया जा सकता है। यहां एक एसपी पदस्थ होगा, जिसके अधीन एक एएसपी ग्रामीण काम करेंगे। इस प्रस्तावित नक्शे के तहत अभनपुर, मुजगहन, नवापारा, वापारा, आरंग, विधानसभा, खरोरा, तिल्दा-नेवरा और धरसींवा थाने ग्रामीण एसपी के अधीन आ सकते हैं। इन थानों को सीएसपी विधानसभा और सीएसपी आरंग के अंतर्गत पुनर्गठित करने की भी चर्चा है। वहीं शहर के भीतर सीएसपी कोतवाली, उरला, आजाद चौक, माना, पुरानी बस्ती और नवा रायपुर के अधीन कामकाज बांटकर उन्हें मजबूत बनाया जाएगा।

नवा रायपुर को शामिल करना अनिवार्य

कमेटी का एक अहम काम होगा यह तय करना कि कमिश्नर प्रणाली का दायरा कहां तक होगा। फिलहाल माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा, लेकिन नवा रायपुर को इसमें शामिल करना अनिवार्य होगा। अभी यह क्षेत्र राखी और मंदिरहसौद थानों के अधीन है। संकेत हैं कि इन दोनों थानों को शहरी थानों में बदला जा सकता है।

सीपी प्रणाली में नए पद

कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर पुलिस संरचना में भी बड़े बदलाव होंगे। प्रस्ताव के मुताबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) -1 पद (आईजी रैंक) जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर - 2 पद (एसएसपी या एसपी स्तर) डीसीपी (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) 4 पद (एएसपी स्तर) इनके अधीन सीएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी कार्य करेंगे। इससे शहर की पुलिसिंग अधिक केंद्रीकृत और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

कमेटी करेगी खाका तैयार

शासन द्वारा गठित सात सदस्यीय कमेटी यह तय करेगी कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी का स्वरूप कैसा होगा। इसमें अधिकार क्षेत्र, जिम्मेदारियां, पदों की संख्या, बल का आकार, कोर्ट और अभियोजन व्यवस्था जैसे बिंदुओं पर सुझाव दिए जाएंगे। समिति की रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा।

नवीन मार्केट को 10 मंजिला शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी

43 कारोबारियों और रोड चौड़ीकरण से प्रभावितों को भी दुकानें

रायपुर। शहर के बीचोंबीच स्थित नवीन मार्केट अब इतिहास बनने की ओर है। नगर निगम ने इस करीब 50 साल पुराने व्यापारिक केंद्र को तोड़कर यहां 10 मंजिला अत्याधुनिक शॉपिंग मॉल खड़ा करने की योजना बनाई है। महापौर मीनल चौबे ने इसके लिए मार्केट के 43 कारोबारियों को बुलाकर इस महत्वाकांक्षी योजना को साझा किया। बैठक में यह भी साफ किया गया कि रोड चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानदारों को भी इस नये मॉल में जगह दी जा सकती है। यानी एक ओर स्वरूप में व्यापार का अवसर मिलेगा, वहीं सड़क चौड़ीकरण से प्रभावितों को भी राहत का रास्ता खुल सकता है। नवीन मार्केट का निर्माण सन 1973 में किया गया था। उस दौर में यह परिसर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। कपड़े से लेकर घरेलू सामान और खानपान तक, हर तरह की दुकानें यहां मिलती थीं। यह सिर्फ बाजार नहीं था, बल्कि शहरवासियों की सामाजिक मुलाकातों का ठिकाना भी रहा। लेकिन वक्त बदलने के साथ बाजार का ढांचा जर्जर हुआ और व्यापार का स्वरूप भी बदल गया। अब जरूरत है एक ऐसे परिसर की, जो बहुउद्देशीय और आधुनिक हो। महापौर चौबे ने बैठक में कहा 'नवीन मार्केट उस जमाने में गौरवशाली केंद्र था। आज इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर शहर की नई जरूरतों के हिसाब से विकसित करना जरूरी है। निगम इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहा है।'

4.62 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक मॉल

नगर निगम के पास कुल 4.62 एकड़ जमीन है। योजना के मुताबिक, मार्केट के पीछे की खाली जमीन और पुराने स्कूल की भूमि को मिलाकर एक विशाल परिसर विकसित किया जाएगा। इसमें व्यापार जगत की सभी सुविधाएं होंगी, साथ ही नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। बैठक में अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, मुख्य अभियंता यूके धलेंद्र, अधीक्षण अभियंता संजय बागडे और पी. राजेश नायडू सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती पर उठे सवाल, पुलिस करेगी जांच

रायपुर/ शहर सत्ता। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले का सबसे पहले खुलासा शहर सत्ता अखबार ने किया था। अब सरकार ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

अभ्यर्थियों ने लगाए गड़बड़ी के आरोप

भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि चयन सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। उनका कहना है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर अपात्र लोगों का चयन किया गया। इसी मुद्दे पर अभ्यर्थी लगातार विरोध जता रहे थे।

पुलिस जांच से होगा खुलासा

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पुलिस जांच से यह तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया में वास्तव में कितनी गड़बड़ी हुई है। जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साप्ताहिक शहर सत्ता

मैनपुर के मटाल इलाके में बड़ी कामयाबी, सर्चिंग अभियान जारी

जंगल में मुठभेड़, एक करोड़ के कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर

गरियाबंद/ मैनपुर। मैनपुर थाना क्षेत्र के मटाल जंगल इलाके में गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में अब तक बड़े कमांडर सहित 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। कहा जा रहा है कि मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली कमांडर मनोज उर्फ मॉडेम, बालकृष्ण उर्फ भास्कर और मंडल कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पांड भी मारा है, गया हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

गरियाबंद एडिशनल एसपी जितेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि इस मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली मार गिराए गए हैं। सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, लेकिन अंधेरा होने के कारण आगे की जानकारी मिलना कठिन हो रही है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। बल तैनात किए जा रहे हैं। ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है। पुलिस ने कहा है कि अभियान समाप्त होने के बाद पूरी जानकारी मीडिया को साझा की जाएगी। हथियार बरामद हुए : ऑपरेशन में फोर्स को ऑटोमेटिक वेपन एक-47, सहित कई हथियार और समग्री बरामद हुई है। साथ ही कुछ दस्तावेज रजिस्टर भी बरामद होने की जानकारी मिली है। जिससे आने वाले समय में कई खुलासे होंगे। संयुक्त अभियान में शामिल कई सुरक्षा बल : गोपनीय सूचना के आधार पर सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा, गरियाबंद ई-30 और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार सुबह मटाल जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया। इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों का अभियान क्षेत्र में जारी है और सघन सचिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने लगातार इस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी रखा है और हर संदिग्धों पर नजर है। पिछले कुछ दिनों से फिर इस इलाके में नक्सली गतिविधियों की जानकारी लगने पर पुलिस की टीम कल रात में ही क्षेत्र में पहुंच चुकी थी और पूरे रणनीति के साथ चारो तरफ से नक्सलियों को घेरा गया है।

मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत का संकल्प

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरियाबंद एवं नारायणपुर जिलों में नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता पर सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के जवानों को बधाई दी है। गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली ढेर किए गए हैं। इनमें 1 करोड़ के इनामी और केंद्रीय समिति सदस्य मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज भी शामिल है। यह नक्सल उन्मूलन अभियान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी क्रम में नारायणपुर जिले में भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की राह चुनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा विश्वास है कि मार्च 2026 तक 'नक्सलमुक्त भारत' का संकल्प साकार होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ रुपए के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें।

एक करोड़ की इनामी मास्टरमाइंड सुजाता का आत्मसमर्पण

जगदलपुर। एक करोड़ की इनामी शीर्ष महिला माओवादी कल्पना उर्फ सुजाता ने हथियार डाल दिए हैं। 62 वर्षीय सुजाता का आत्मसमर्पण माओवादी हिंसक संगठन की रीढ़ पर बड़ा प्रहार है। वह दिवंगत शीर्ष माओवादी किशनजी की पत्नी और बसव राजू के बाद महासचिव बनने की दौड़ में सबसे आगे खड़े भूपति की भाभी है। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में शनिवार को मुख्यधारा में लौटी सुजाता को वहां की सरकार ने 25 लाख रुपये की इनामी राशि और पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आदिवासी अंचलों में पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसे 100 से अधिक माओवादी घटनाओं की मास्टरमाइंड मानती रही हैं। 2010 के ताड़मेटला नरसंहार में 76 जवान बलिदान हुए थे। साल 2013 में झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हत्या हुई और 2020 के मिनपा हमले समेत कई बड़े हमलों के पीछे उसका दिमाग माना जाता है। सुजाता का जन्म 1963 में तेलंगाना में हुआ। उसके पिता तिम्मा रेड्डी पोस्टमास्टर थे। दिसंबर 1982 में उसने पीपुल्स वार ग्रुप का दामन थामा और सांस्कृतिक इकाई जाना नाट्य मंडली में सक्रिय हुई।

सीएस और डीजीपी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में उलझन

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन में मुख्य सचिव और डीजीपी के पद पर सरकार अब तक निर्णय नहीं ले पाई है। दोनों महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार उलझ गई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की पिछले तीन माह से दोंनो पदों पर प्रभारी, प्रशासनिक सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें तीन माह के लिए कामकाज पर एक्सटेंशन दिया गया था, पड़ रहा असर जो इसी माह पूरा हो रहा है। एक्सटेंशन की अवधि दो सप्ताह बाद पूरी हो जाएगी। अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि उन्हें दोबारा एक्सटेंशन देने केंद्र को पत्र लिखा जाएगा या सीएस के पद पर नई नियुक्ति होगी। बताया जाता है कि सीएस के पद पर अमिताभ जैन को दोबारा एक्सटेंशन देने पर विचार हो सकता है। डीओपीटी के नियमानुसार राज्य सरकार की ओर से आवेदन देने पर ही विचार होगा। जीएडी की ओर से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। वहीं सीएस पद के लिए सुब्रत साहू, रेणु पिल्ले, अमित अग्रवाल, ऋचा शर्मा दावेदार बताए जाते हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर निर्णय होगा। राज्य में प्रशासन के दो प्रमुख पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति न होने से प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

पूर्णकालिक डीजीपी का इंतजार

छत्तीसगढ़ में डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्य शासन ने अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी के पद पर नियुक्त किया। डीजीपी पद के लिए हुई डीपीसी के बाद यूपीएससी ने चार नामों के पैनल में दो नामों को हरी झंडी दी थी। इनमें अरुण देव गौतम के अलावा हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल था।

तीन दर्जन और पदों पर भाजपा नेताओं को मिलेगा मौका

नवरात्रि पर मिल सकता है निगम मंडल में बचे पदों का तोहफा

रायपुर। प्रदेश सरकार ने डेढ़ साल बाद जाकर पिछली बार नवरात्रि के समय अप्रैल में निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड में तीन दर्जन नियुक्तियों की थीं। अब एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि पर बचे हुए निगम, मंडल, आयोग के तोहफा मिल सकता है। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव को नई कार्यकारिणी के ऐलान के बाद अब जहां विधायकों की नजरें संसदीय सचिवों के पदों पर हैं, वहीं निगम, मंडल और आयोग में बचे पदों को लेकर भी भाजपा नेता इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश प्रवास से भी लौट चुके हैं। अब जल्द ही बची नियुक्तियों का ऐलान होने की संभावना है।

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अप्रैल में प्रदेश सरकार ने 34 निगम, मंडलों के 36 पदों पर भाजपा नेताओं की नियुक्तियां कीं। इनमें से आधा दर्जन नेताओं के पदों पर पेंच भी फंसा गया था, ऐसे में इनका पदभार संभालना मुश्किल हो गया तो अंततः प्रदेश सरकार ने इनको दूसरे निगम, मंडल में कुर्सी देने का काम किया है। इसके बाद एक केश शिल्पी बोर्ड की अध्यक्ष मोना सेन को छोड़कर सभी ने पदभार भी संभाल लिया है।

इनमें नियुक्ति अभी बाकी

जिन निगम, मंडलों में अभी नियुक्ति बाकी है उनमें मार्कफेड, लघु वनोपज सहकारी संघ. फिलम विकास निगम, मत्स्य महासंघ, हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ सिंधी अकादमी और सहकारी संघ शामिल हैं। इसी के साथ पांच जिलों के सहकारी केंद्रीय बैंक और चार शक्कर कारखानों में भी अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल जैसे निगम, मंडलों में उपाध्यक्षों के साथ सदस्यों के पद भी खाली हैं। इनकी संख्या भी डेढ़ दर्जन से ज्यादा है।

दुर्ग में धर्मांतरण पर हंगामा, पुलिस ने स्थिति संभाली

दुर्ग। शहर के पद्मनाभपुर इलाके में रविवार को धर्मांतरण के आरोप को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। एक घर में चल रही प्रार्थना सभा की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और सभा को रुकवाने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हो गई। सूत्रों के मुताबिक बाफना मंगलम के पास एक मकान में प्रार्थना सभा हो रही थी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसी दौरान झड़प हो गई और मारपीट की नौबत आ गई। बजरंग दल की ओर से जॉन नामक व्यक्ति पर धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल होने और बाहरी फंडिंग प्राप्त करने का आरोप लगाया गया।

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमर्जी और प्रयोग पड़ रहे पढ़ाई पर भारी

प्रिंसिपल, प्रोफेसर की कमी तो कैसे मिलेगी रैंकिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता की पोल एनआईआरएफ ने खोलकर रख दी है। प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज की रैंकिंग बेहद खराब आई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रोफेसरों और प्रिंसिपल की कमी सामने आई है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों के सैकड़ों पद खाली हैं जो भरे नहीं जा सके हैं। वहीं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भी भारी कमी है। इन सबके बीच उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमर्जी और प्रयोग भी शिक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। इस संबंध में जानकारी के अनुसार एनआईआरएफ रैंकिंग में टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरिच, परशेप्शन आदि पैरामीटर देखे जाते हैं। लेकिन यहां तो उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यवस्था का बुरा हाल है। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टॉफ की कमी, रिसर्च पेपर आदि को लेकर स्थिति कमजोर है।

एनईपी, एमओयू, स्टार्टअप में बीत रहा समय

इस दिनों उच्च शिक्षा विभाग और प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों का पूरा फोकस एनईपी, एमओयू और स्टार्टअप पर है। इन्हें लेकर कार्यशाला, ऑनलाइन बैठक, ऑफलाइन बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। एमओयू के लिए बड़े-बड़े आयोजन हो रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों के यूनिवर्सिटी और संस्थानों से एमओयू किए जा रहे हैं। रिसर्च और शिक्षा गुणवत्ता की बात हो रही है लेकिन उसकी हकीकत रैंकिंग से सामने आ गई है।

प्रिंसिपल और प्रोफेसरों की कमी

300 टॉप कॉलेजों में छत्तीसगढ़ के एक भी कॉलेज के नहीं होने के पीछे शिक्षाविद सबसे बड़ी वजह प्रिंसिपल और प्रोफेसरों की कमी को बताते हैं। उनका कहना है कि वर्षों से पद खाली पड़े हैं। पीएससी के माध्यम से प्रोफेसरों के पद निकाले गए हैं लेकिन कई वर्षों में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अधिकांश कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। प्रभार देने में भी राजनीति होती है। प्रदेश में रिसर्च, इनोवेशन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी यहां तक लॉ संस्थानों की हालत रैंकिंग के हिसाब से बेहद खराब है। एक भी लॉ में सिर्फ दो संस्थानों ने पार्टिसिपेट किया है। कॉलेजों को तो रिसर्च, इनोवेशन, इंजी., फार्मसी, छोड़ दें एचएनएलयू तक ने लॉ की हालत चिंतनीय है।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

जरुरी या मज़बूरी..

क्या वाकई भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना मज़बूरी है या फिर मुनाफ़ाख़ोरी की बुरी लत? पहलगाम में 26 लोग मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में कई जवानों की जान गई। इसके बावजूद मैच कराया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह कि बीसीसीआई और भारत सरकार को इसमें आपत्ति भी नहीं। पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी बोलीं बॉयकाट करें एशिया कप क्रिकेट मैच। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्लब, पब और रेस्टोरेंट्स को मैच न दिखाने की चेतावनी दी है। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो मैच क्यों हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा- पहलगाम में जो हुआ इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भारत-पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले के प्रसारण को रोकने की अपील की है। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, 'भारतीय सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसे में क्रिकेट मैच खेलना देशभक्ति का मजाक है। देश के 57 फीसदी लोगों का मत है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच भारत को नहीं खेलना चाहिए। इसी तरह 39 प्रतिशत चाहते हैं खेल को दुर्भावनाओं से अलग रखना चाहिए। जबकि 4 परसेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता खेलें या नहीं खेलें।

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विरोध के स्वर मुखर हैं तो बचाव में उतरे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा- "जब एसीसी या आईसीसी के बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो देशों के लिए भाग लेना मजबूरी और जरूरी होता है। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा।" वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितीश राणे ने उद्धव ठाकरे के बयान का जवाब दिया। कहा, "आदित्य ठाकरे खुद बुर्का पहनकर ये मैच देखेंगे और पाकिस्तान के नारे भी लगाएंगे।" ऐसे में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद, हिंसा और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम हमले में भारत एकजुट दीखता है लेकिन, दोनों देशों के क्रिकेट वायरस से इफेक्टेड सरकार और बीसीसीआई मुंह में दही जमाये है। एसीसी या आईसीसी टूर्नामेंट के नियमों का हवाला देते हुए मैच होने देने की चाह रखने वाले पाकिस्तान के साथ भारत के खेलने को जरुरी मानते हैं या मज़बूरी अब भी बड़ा सवाल है।

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-आज राजभाषा हिंदी दिवस के बेरा म मैं ए जानना चाहत हौं जी भैरा के तुँहर महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी ल एकर ले का फायदा होइस?

-हम अपन देश के संविधान के सम्मान करथन जी कोंदा, तेकर सेती हमर देश के राजभाषा हिंदी के घलो सम्मान करथन, तभो ए करू अनुभव ल घलो कहे बर नइ घेपन, के हमर संग हिंदी के नॉव म अन्याय जादा होय हे.

-तुँहला अइसे काबर जनाथे संगी?

-अब देख- छत्तीसगढ़ म छत्तीसगढ़ी मातृभाषा बोलइया मन के संख्या 65.83 प्रतिशत हे, अउ हिंदी मातृभाषा वाले मन के संख्या मात्र 5.65 प्रतिशत, तभो ले षड्यंत्र पूर्वक हमर ए राज ल हिंदी भाषी घोषित कर दिए गिस.. एकर दुष्परिणाम ए होइस के हमला हिंदी के नॉव म आने हिंदी भाषी राज मन के इतिहास, संस्कृति अउ गौरव मनला बरपेली पढ़ाए गिस, हमर ऊपर लादे गिस.. अउ हमर छत्तीसगढ़ के असली संस्कृति, इतिहास अउ गौरव ल हमर ले दुरिहा राखे खातिर तोपे अउ लुकाए गिस.. एकर दुखद परिणाम ए होइस के हम अपन गौरव ल भुला के आने मन के गौरव अउ संस्कृति ल मुड़ म लादे किंजरे लागेन.. उँकर गुलामी भोगे बरोबर उँकर पिछलग्गू बनत गेन.. परिणाम तुँहर आगू म हे.. बाहिर के लोगन इहाँ अगुवा बनत गिन अउ हम उँकर बनिहार.

2030 तक दुनिया का हर पांचवां व्यक्ति बोलेगा हिंदी

प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी

भाषा संवाद संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। मनुष्य को इसलिए भी परमात्मा की श्रेष्ठ कृति कहा जाता है कि वह भाषा का उपयोग कर अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। यही विशेषता है, जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करती है।हिंदी एक बहुआयामी भाषा है। यह बात इसके प्रयोग क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए भी समझी जा सकती है। यह अलग बात है कि हिंदी भाषा की बात करते समय हम सामान्यतः हिंदी साहित्य की बात करने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि साहित्यिक हिंदी, हिंदी के विभिन्न आयामों में से एक है, लेकिन यह केवल हिंदी के एक बड़े मानचित्र का छोटा-सा हिस्सा है, शेष आयामों पर कम विचार हुआ है और व्यावहारिक हिंदी की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए तो और भी कम विमर्श हमारे सामने हैं। यदि हिंदी भाषा के आंतरिक इतिहास का उद्घाटन करना हो तो नामकरण ही उसका आधार बन सकता है। हिंदी, हिंदवी, हिन्दुई और दकिनी के विकास क्रम में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अलग-अलग समय में एक ही भाषा के भिन्न नाम प्रचलित रहे हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। यह करीब 11वीं शताब्दी से ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। उस समय भले ही राजकीय कार्य संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में होते रहे हों, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र में आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार, विमर्श, जीवन और व्यवहार का माध्यम हिंदी ही रही है।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से ही संपूर्ण राष्ट्र से सम्पर्क किया और सफलता हासिल की। इसी कारण आजादी के पश्चात संविधान-सभा द्वारा बहुमत से 'हिंदी' को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय किया था। जैसे-जैसे भाषा का विस्तार क्षेत्र बढ़ता जाता है, वो भाषा उतने ही अलग-अलग रूप में विकसित होना शुरू हो जाती है, यही हिंदी भाषा के साथ हुआ, क्योंकि यह भाषा पहले केवल बोलचाल की भाषा तक ही सीमित थी। उसके बाद साहित्यिक भाषा के क्षेत्र में इसे जगह मिली, और फिर समाचार-पत्रों में 'हिंदी पत्रकारिता' का विकास हुआ। अपनी अनवरत यात्रा के कारण स्वतन्त्रता के बाद हिंदी, भारत की राजभाषा घोषित की गई तथा उसका प्रयोग कार्यालयों में होने लगा और हिंदी का एक राजभाषा का रूप विकसित हुआ।

अगर हम आंकड़ों में हिंदी की बात करें तो 260 से ज्यादा विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 64 करोड़ लोगों की हिंदी मातृभाषा है। 24 करोड़ लोगों की दूसरी और 42 करोड़ लोगों की तीसरी भाषा हिंदी है। इस धरती पर 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलने और समझने में सक्षम हैं। 2030 तक दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति हिंदी बोलेगा। यूएई और फिजी जैसे देशों में हिंदी को तीसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 18 हजार शब्द हिंदी के शामिल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो तीन साल पहले अंग्रेजी इंटरनेट की सबसे बड़ी भाषा थी, अब हिंदी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। गूगल सर्वेक्षण बताता है कि इंटरनेट पर डिजिटल दुनिया में हिंदी सबसे बड़ी भाषा है।

अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी ही हमारी राजभाषा क्यों? इसका जवाब बहुत पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के लिए तीन लक्षण बताए थे। पहला कि वो भाषा आसान होनी चाहिए। दूसरा प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। और तीसरा उस भाषा को बोलने वालो की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगर ये तीनों लक्षण किसी भाषा में थे, हैं और रहेंगे, तो वो सिर्फ हिंदी भाषा ही है। आज भाषा को लेकर संवेदनशील और गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस सवाल पर भी सोचना चाहिए कि क्या अंग्रेजी का कद कम करके ही हिंदी का गौरव बढ़ाया जा सकता है? जो हिंदी कबीर, तुलसी, रैदास, नानक, जायसी और मीरा के भजनों से होती हुई प्रेमचंद, प्रसाद, पंत और निराला को बांधती हुई, भारतेंदु हरिशचंद्र तक सरिता की भांति कलकल बहती रही, आज उसके मार्ग में अटकले क्यों हैं?

यदि हम सच में चाहते हैं कि हिंदी भाषा का प्रभुत्व राजभाषा के रूप में बना रहे, तो हमें इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना होगा। सरकारी कामकाज में हिंदी को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे में भरोसा फिर उन्हीं नौजवानों का करना होगा, जो एक नए भारत के निर्माण के लिए तैयार हैं। जो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। भरोसे और आत्मविश्वास से दमकते ऐसे तमाम चेहरों का इंतजार भारत कर रहा है। ऐसे चेहरे, जो भारत की बात भारत की भाषाओं में करेंगे। जो अंग्रेजी में दक्ष होंगे, किंतु अपनी भाषाओं को लेकर गर्व से भरे होंगे। उनमें 'एचएमटी' यानी 'हिंदी मीडियम टाइप' या 'वर्नाकुलर पर्सन' कहे जाने पर हीनता पैदा नहीं होगी, बल्कि वे अपनी भाषा से और अपने काम से लोगों का और दुनिया का भरोसा जीतेंगे।

हिंदी और भारतीय भाषाओं के इस समय में देश ऐसे युवाओं का इंतजार कर है, जो अपनी भारतीयता को उसकी भाषा, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति के साथ समग्रता में स्वीकार करेंगे। जिनके लिए परंपरा और संस्कृति एक बोझ नहीं, बल्कि गौरव का कारण होगी। यह नौजवानी आज कई क्षेत्रों में सक्रिय दिखती है। खासकर सूचना-प्रौद्योगिकी की दुनिया में। जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया, कि सूचना-प्रौद्योगिकी की दुनिया में बिना अंग्रेजी के गुजारा नहीं है। ये लोग ही हमें भरोसा जगा रहे हैं। ये भारत को भी जगा रहे हैं। आज भरोसा जगाते ऐसे कई दृश्य हैं, जिनके श्रीमुख और कलम से व्यक्त होती हिंदी देश की ताकत है।

विकसित देश में भी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम जनता

यह विचित्र है कि फ्रांस जैसे विकसित देश में भी सरकार की वैसी नीतियों के खिलाफ आम जनता को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें आरोप के मुताबकि, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। गौरतलब है कि राजनीतिक अस्थिरता को झेलते फ्रांस में बजट कटौती को लेकर पहले ही विरोध का माहौल बना हुआ था। ऐसे में दो राष्ट्रीय छुट्टी को रद्द करने, 2026 में पेंशन पर रोक लगाने और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में अरबों डालर की कटौती करने जैसे प्रस्तावों ने लोगों के भीतर व्यापक आक्रोश पैदा किया।

इन सबको फ्रांस के लोग कार्य-संस्कृति और सेहत के मुद्दे के साथ खिलवाड़ के तौर पर देख रहे हैं और सरकार की ओर से मिलने वाली सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों के दौरान फ्रांस में अलग-अलग मुद्दों पर जिस तरह जनाक्रोश और व्यापक पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे गए, एक तरह से उसी की अगली कड़ी की तरह इस बार भी 'सब कुछ रोक दो' के नारे के तहत भारी संख्या में लोगों का सड़कों पर उतर आना कोई हैरानी की बात नहीं है।

फ्रांस में पहले भी भड़क चुकी है हिंसा

यह समझना मुश्किल है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपनी सरकार के खिलाफ बार-बार आंदोलन की वजहों पर विचार करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि फ्रांस में लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क गया है और सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन दिख रहे हैं। इससे पहले भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई ऐसे मौके आए, जब सरकार के नीतिगत फैसलों के जनता पर पड़ने वाले विपरीत असर के मद्देनजर वहां व्यापक जनाक्रोश उभरा और नतीजतन भारी पैमाने पर हिंसा देखी गई। पेंशन मिलने की उम्र बढ़ाने, ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी, लैंगिक समानता और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने जैसे मुद्दों पर भी वहां कई बार आंदोलन हुए हैं। विडंबना यह है कि बार-बार लोगों के विरोध और उसकी व्यापकता के बावजूद फ्रांस की सरकार को शायद इस बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं लग रही कि आखिर नीतियां बनाने या कोई नीतिगत फैसले लेने में उससे कौन-सी चूक हो रही है, जिससे लोगों के बीच नाराजगी फैलती है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

मैं शिव भक्त, सारा जहर निगल जाता हूं : PM मोदी

असम में 18,530 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर मिशन पर असम पहुंचे और रविवार (14 सितंबर) को 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. असम के दरांग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव के भक्त हैं और दुश्मनों द्वारा दिया गया सारा जहर सह ले सकते हैं.

शिव का भक्त हूं, सारा जहर निकाल लेता हूं

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे कितनी भी गालियां दी जाएं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं और सारा जहर निकाल लेता हूं. लेकिन किसी और का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता. भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने अपमान किया, यह गलत है. डबल इंजन सरकार असम और उसके लोगों के सपनों को पूरा करने में पूरी निष्ठा से जुटी है."

असम को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि 1962 के चीन युद्ध के बाद उत्तरपूर्व के लोगों के घाव अभी भी भरे नहीं हैं. उन्होंने असम के विकास पर जोर देते हुए कहा, "भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है और असम भी इसमें अग्रणी है. कभी संघर्षरत असम अब 13% की विकास दर के साथ उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. यह लोगों की मेहनत और भाजपा की डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है."पीएम मोदी ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा. उन्होंने कहा कि इस पवित्र धरती पर आकर उन्हें एक अलग पुण्य अनुभव हो रहा है.

कांग्रेस पर भूपेन हजारिका के अपमान का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर असम के प्रसिद्ध कलाकार भूपेन हजारिका का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत रत्न देने पर तंज कसते हुए कहा था कि "मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है."

विकास और स्वदेशी पर जोर

पीएम मोदी ने जनसभा में लोगों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने कहा, "जो भी खरीदोगे, स्वदेशी ही खरीदो. अगर किसी को तोहफा देंगे, तो वह मेड इन इंडिया होना चाहिए, जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए."

मेरे दिमाग की कीमत 200 करोड़ महीना : नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल (E-20 Petrol) से निजी लाभ के आरोपों को खारिज किया है. इन दिनों इसे लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और विपक्ष गडकरी पर आरोप लगा रहा है. इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि उनका दिमाग ही 200 करोड़ प्रति माह का है और पैसों के लिए कभी भी अपना लेवल नहीं डाउन कर सकते. नागपुर के एग्रीकॉस वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में बोलते हुए शनिवार (13 सितंबर, 2025) को गडकरी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'आपको लगता है कि मैं यह सब पैसे के लिए कर रहा हूं? लेकिन, मैं ईमानदारी से कमाना जानता हूं. हमारे विचार किसानों के हित के लिए हैं, न कि जेब भरने के लिए. मेरा भी एक परिवार और एक घर है, मैं कोई संत नहीं हूं.'

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता अक्षय मल्होत्रा ने वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से कहा था कि ये एथेनॉल ब्लेंड के खिलाफ नहीं, बल्कि उपभोक्ता की पसंद को सुरक्षित रखने और उन्हें विकल्प मुहैया कराने के बारे में है. याचिका में कहा गया कि सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद बने वाहन ही E-20 पेट्रोल के अनुकूल हैं, जबकि जबकि पुराने मॉडल के लिए जोखिम है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

सरकार एथेनॉल को पेट्रोल का एक स्वच्छ और सस्ता विकल्प बता रही है. वहीं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे वाहनों की क्षमता प्रभावित हो सकती है. एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के इस्तेमाल से वाहनों के नुकसान के सवालों को नितिन गडकरी ने राजनीति से प्रेरित एक पेड कैंपेन करार दिया था.

वक्फ संशोधन कानून होगा लागू या लगेगी रोक?

सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (15 सितंबर, 2025) को आदेश देगा. मामले में अंतरिम राहत के मुद्दे पर कोर्ट ने 22 मई को आदेश सुरक्षित रखा था. चीफ जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने लगातार 3 दिन सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि संसद से बने कानून को अंतिम फैसला होने तक संवैधानिक माना जाता है. उसके प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए बहुत मजबूत आधार की जरूरत पड़ेगी.

वक्फ बोर्ड को दावे से रोकने जैसी बातों का विरोध

याचिकाकर्ता पक्ष ने वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने, सरकार के साथ वक्फ बोर्ड के विवाद में फैसला सरकारी अधिकारी के हाथों में होने, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने, प्राचीन स्मारकों में धार्मिक गतिविधि में समस्या की आशंका, वक्फ करने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त और आदिवासी जमीन पर वक्फ बोर्ड को दावे से रोकने जैसी बातों का विरोध किया है.

इन्हें मुसलमानों से भेदभाव और धार्मिक मामलों में दखल बताया है. दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने संसद की तरफ से पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद कानून बनाने का हवाला दिया. केंद्र ने कहा कि अंतिम सुनवाई से पहले कानून की धाराओं पर रोक लगाना सही नहीं होगा.

जो लोग यहां याचिका लेकर आए हैं, वह व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं हैं. वह पूरे मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि नहीं हैं. कानून सार्वजनिक हित मे बनाया गया है. पुराने वक्फ कानून की विसंगतियों को दूर किया गया है.

वक्फ करने के लिए रखी गई ये शर्त

सरकार ने कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. इसे मौलिक अधिकारों जैसा दर्जा नहीं दिया जा सकता. वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को 1923 के कानून में भी जरूरी रखा गया था. 102 साल से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वही अब भी विरोध कर रहे हैं. अगर संपत्ति उनकी नहीं है तो सामाजिक हित में उसका इस्तेमाल होना चाहिए. केंद्र ने यह दलील भी दी कि पहले वक्फ सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता था, लेकिन वक्फ कानून 2013 में गैर मुस्लिमों की संपत्ति के भी वक्फ होने का प्रावधान रख दिया गया था. इसे सुधारते हुए वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल मुस्लिम होने की शर्त रखी गई है. आदिवासियों की जमीन को संविधान भी संरक्षण देता है.

भगोड़े जाकिर नाइक को हुई 'लाइलाज बीमारी'

कुवालालांपुर। मलेशिया में विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को गंभीर बिमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भगोड़े जाकिर नाइक को लाइलाज वायरल इंफेक्शन होने की खबर सामने आ रही है इसलिए उसे कुआलालंपुर के पास सनवे मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए लाया गया है. हालांकि, उसकी सेहत के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. न चूंकि यह मामला धार्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर काफी संवेदनशीलता है जिस वजह से इसे जानबूझकर गोपनीय रखा जा रहा है. जाकिर नाइक जिस अस्पताल में भर्ती है वह कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इंफेक्शियस डिजीज और एचआईवी केयर जैसी स्पेशियलिटी के लिए मशहूर है. यह अस्तपाल वीआईपी लोगों के इलाज के लिए मशहूर है.जाकिर नाइक पहले भी मलेशिया में इलाज करा चुका है. हालांकि इस बार उनकी बीमारी काफी गंभीर बताई जा रही है।

भारत के बाद अब ट्रंप के निशाने पर चीन

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO से चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपील की है. उनका मानना है कि इससे चीन की रूस पर आर्थिक पकड़ कमजोर होगी और यूक्रेन युद्ध का अंत होगा. इसके साथ ही उन्होंने सभी NATO देशों से रूस से तेल खरीदना बंद करने और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

चीन पर टैरिफ लगाने की अपील

ट्रंप ने शनिवार को NATO देशों को एक पत्र लिखकर कहा कि अगर सभी सदस्य देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो वे भी रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को तैयार हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा, "मैं तैयार हूं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए, लेकिन तभी जब सभी NATO देश एकमत होकर ऐसा कदम उठाएं." डोनाल्ड ट्रंप की यह अपील पिछले महीने लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ से जुड़ी हुई है, जो उन्होंने भारत पर लगाया था. इसका कारण भारत की लगातार रूस से तेल आयात करना बताया गया था. हालांकि चीन पर अभी तक इसी तरह की कोई टैरिफ कार्रवाई नहीं की गई है।

भारत के खिलाफ नेपाल के लोगों को भड़का रहा पाकिस्तान

नई दिल्ली। नेपाल में हालिया हिंसा और सत्ता परिवर्तन के बीच पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चला रहा है. भारतीय खुफिया एजेंसियों की मॉनिटरिंग में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना 9 सितंबर से सोशल मीडिया पर लगातार नेपाल में भारत-विरोधी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक, मॉनिटरिंग में सामने आया है कि पाकिस्तान 9 सितंबर से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि नेपाल में आगजनी और सत्ता परिवर्तन के पीछे भारत है और ये झूठा प्रोपेगेंडा नेपाल के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पाकिस्तानी सेना और ISI के बॉट एकाउंट्स पोस्ट में नेपाल में ट्रेंड हो रहे हैशटैग भी उपयोग कर रहे हैं, ताकि नेपाल की जनता तक भारत के खिलाफ उसका झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके. भारत के खिलाफ नेपाल के लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर फैलायी जा रही झूठी कैंपेन की जब एबीपी न्यूज ने कीवर्ड और हैशटैग एनालिसिस की तो सामने आया कि 9 सितंबर से 11 सितंबर तक 85 हजार से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से भारत के खिलाफ नेपाल में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिसकी कुल रीच 72 लाख से अधिक थी. साथ ही इस कैंपेन में ISI ने हिंदू नाम वाले बोट्स अकाउंट्स का भी प्रयोग किया था, जिससे ऐसा लगे कि पोस्ट नेपाल या भारत के लोग भी कर रहे हैं.

पाकिस्तान से ऑपरेट 82 प्रतिशत अकाउंट्स

भारत के खिलाफ चलाए गए इस झूठे प्रोपेगेंडा की एनालिसिस में ये भी सामने आया कि भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव में 82 प्रतिशत अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे, वहीं पांच प्रतिशत बांग्लादेश और इंडोनेशिया से चलाए जा रहे हैं.

पहले वनडे में भारत को मिली 8 विकेट से करारी शिकस्त

चंडीगढ़। महिला वर्ल्ड कप 2025 से पहले टीम इंडिया अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का पहला मैच चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम ने भले ही बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर सका.

भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया दम

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय कप्तानी वाली हरमनप्रीत कौर की टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 281 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 63 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. वहीं, प्रतीका रावल ने 96 गेंदों पर 64 रन ठोके. इस दौरान उन्होंने 6 चौके लगाए. इसके बाद हरलीन देओल ने 57 गेंदों पर 54 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया. रिचा घोष ने भी 20 गेंदों पर 25 रन जोड़े, जबकि दीप्ति शर्मा 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद रहीं.

ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेज किया टारगेट

इस टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की ओर से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट गंवाते हुए 44.1 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया. इस दौरान ओपनर फीबी लिचफील्ड ने एक दमदार पारी खेली. उन्होंने 80 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए. इस दौरान फीबी लिचफील्ड ने 14 चौके लगाए. वहीं, कप्तान एलिसा हीली ने 23 गेंदों पर 27 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. एलिस पेरी ने भी 38 गेंदों पर 30 रनों का योगदान दिया।

भारतीय बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने रचा इतिहास

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

नई दिल्ली। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर जैस्मिन लंबोरिया बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में पोलैंड की जूलिया स्जेरेमेटा को हराकर इतिहास रचा. पोलैंड की इस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था. फाइनल की बात करें तो लंबोरिया पहले राउंड में पिछड़ रही थी, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने शानदार वापसी की. जैस्मिन ने पोलैंड की मुक्केबाज जूलिया को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. बता दें कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किसी भारतीय पुरुष ने पदक नहीं जीता. 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब पुरुष मुक्केबाज बिना पदक लिए लौटे हैं. जदुमणि सिंह को कजाखस्तान के सांजेर ताशकेनबे ने 4-0 से मात दी. जदुमणि की हार के साथ ये कंफर्म हुआ कि भारतीय पुरुष दल खाली हाथ लौटेगा.

कौन हैं जैस्मिन लंबोरिया?

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जैस्मिन लंबोरिया 24 साल की हैं. उनका जन्म 30 अगस्त, 2001 को हरियाणा के भिवानी में हुआ था. लेंबोरिया एक मुक्केबाज परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन फिर भी एक लड़की के लिए इस खेल में अपने करियर बनाना आसान नहीं था. हालांकि न सिर्फ उन्होंने अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि इस खेल से अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम रौशन किया. जैस्मिन के परदादा हवा सिंह एक हैवीवेट मुक्केबाज और दो बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे.

कॉमनवेल्थ में जीता था ब्रोंज

जैस्मिन लंबोरिया ने इसी साल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भी गोल्ड मेडल जीता था. जैस्मिन ने बिर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2021 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है. शानदार प्रदर्शन के बाद जैस्मिन को भारतीय सेना में शामिल किया गया।

ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका की ही निकाल देगी जान : रंगराजन

नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और वैश्विक उद्योग जगत पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. इस बीच, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियां न सिर्फ वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकती हैं. रंगराजन ने शुक्रवार को 'ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन' के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप की कुछ नीतियों ने ग्लोबल ट्रेड के रुझानों को ठप कर दिया है. उन्होंने 'BRICS' का नाम लिए बिना कहा कि स्वतंत्र व्यापार वाले अलग-अलग गुटों का उभरना अपरिहार्य है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ऐसा विश्व होना चाहिए जिसमें व्यापार अधिक खुला हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका के नीति निर्धारक समझदारी से काम लेंगे और आत्मघाती नीतियों को बदलेंगे।

जीएसटी कम होने के बाद भी FMCG कंपनियां दाम कम करने को नहीं तैयार

नई दिल्ली। उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) ने टैक्स अधिकारियों को साफ कर दिया है कि वे लोकप्रिय कम कीमत वाले उत्पादों पर दाम में कटौती नहीं करेंगी. इनमें 5 रुपये का बिस्किट, 10 रुपये का साबुन और 20 रुपये का टूथपेस्ट जैसे उत्पाद शामिल हैं. जबकि इन पर टैक्स दर में कटौती हुई है, जिसके बाद इनके दाम कम होने चाहिए थे. कंपनियों का तर्क है कि उपभोक्ता इन सामानों को फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने के आदी हैं. अगर इनकी कीमतें घटाकर 9 रुपये या 18 रुपये कर दी जाएं तो उपभोक्ताओं में कन्फ्यूजन पैदा होगा और लेन-देन में असुविधा होगी. इसके बजाय कंपनियों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) को सुझाव दिया है कि वे कीमत जस की तस रखेंगी, लेकिन पैकेट में क्वांटिटी बढ़ा देंगी. यानी अब अगर कोई ग्राहक 20 रुपये का बिस्किट खरीदेगा, तो उसे पहले से ज्यादा मात्रा मिलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, कई बड़े एफएमसीजी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि उसी कीमत में ज्यादा क्वांटिटी देने से उपभोक्ताओं तक कम हुई जीएसटी का फायदा बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएगा.

कंपनियां फायदा आगे देने को तैयार?

बिकाजी फूड्स के सीएफओ रिषभ जैन ने पुष्टि की कि कंपनी छोटे पैकेट्स का वजन बढ़ाएगी ताकि उपभोक्ता को ज्यादा वैल्यू मिल सके. वहीं, डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा कि उनकी कंपनी भी निश्चित रूप से जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देगी।

श्रीलंका ने बांग्लादेश को छह विकेट से हराया

नई दिल्ली। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है. यह श्रीलंका की एशिया कप 2025 में पहली जीत है, दूसरी ओर इस हार के साथ बांग्लादेश के लिए सुपर-4 की राह मुश्किल हो गई है. इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम लड़खड़ाते हुए 139 रन बनाने में सफल रही थी. जवाब में 6 बार की एशिया कप चैंपियन श्रीलंका ने 32 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. बांग्लादेश ने वापसी तो की, लेकिन वो वापसी काम नहीं आई. बांग्लादेश टीम बैटिंग में शुरुआती झटकों के बाद उबर ही नहीं पाई. उसकी पारी के पहले 2 ओवर मेडर रहे, जिनमें नुवान तुषारा और दुश्मंता चमीरा ने मेडन ओवर करते हुए एक-एक विकेट भी लिया. बांग्लादेश का स्कोर 2 ओवर में बिना रन बनाए 2 विकेट हो चुका था. कप्तान लिटन दास कुछ देर क्रीज पर टिके रहे, लेकिन वो भी 28 रन बनाकर चलते बने. बांग्लादेश की आधी टीम 53 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी.

सोना-चांदी खरीदने वालों को राहत!

नई दिल्ली। देश में आज सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 24 कैरेट सोने का भाव कल की ही तरह 1,11,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है. हालांकि, पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. भारत में सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है. लोग इसे सुरक्षित संपत्ति मानते हुए इसमें निवेशक करते हैं. आमतौर पर जियो-पॉलिटिकल टेंशन, घरेलू मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव होता रहता है. सोने की कीमत बदलती रहती है. वर्तमान में, 24 कैरेट सोने की कीमत 11,117 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 10,190 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,337 रुपये प्रति ग्राम है।

धड़ाधड़ फाइल हो रहे रिटर्न, सर्वर ओवरलोड

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का कल 15 सितंबर, 2025 को आखिरी मौका है. अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल कराए जा चुके हैं. अंतिम समय में किसी भी हड़बड़ी से बचने के लिए आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए 24X7 सपोर्ट सर्विस का भी इंतजाम किया है. इस बात को लेकर भी अटकलें तेज है कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे और बढ़ाई जा सकती है. हालांकि, इस बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है.

इस बीच, इनकम टैक्स पोर्टल पर कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं. कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सपेयर्स अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, समस्या पूरे सिस्टम में नहीं है और न ही सभी टैक्सपेयर्स को इसका सामना करना पड़ रहा है. हो सकता है कि एक ही समय में लॉग इन करने की कोशिश कर रहे टैक्सपेयर्स को ऐसी दिक्कतें आ रही हैं. हाई ट्रैफिक के चलते कई बार सर्वर ओवरलोड हो जाता है. चूंकि, रिटर्न फाइल करने में अब बस आज और कल का ही वकत बचा है इसलिए लोग धड़ाधड़ अपना आईटीआर जमा कर रहे हैं. ऐसे में भले ही पोर्टल ठीक से काम करे, लेकिन एक साथ कई सारे टैक्सपेयर्स के अनुरोधों को संभाल नहीं पा रहा है. आप इसे किसी 4-6 लेन वाले हाईवे की तरह से समझिए, जहां ट्रैफिक जाम होने के कारण कुछ गाड़ियां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं कुछ स्पीड में निकल जा रही हैं.

आयकर विभाग ने 13 सितंबर, 2025 को सोशल मीडिया पर कहा था A I S अब किसी भी थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर टूल के जरिए डाउनलोड नहीं किया जा सकता इसलिए अब A I S डाउनलोड करने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले ई-फाइलिंग ITR पोर्टल पर लॉग इन करें और फिर AIS कंप्लायंस पोर्टल (https://ais.insight.gov.in/complianceportal/ais) पर जाएं. हालांकि, कुछ यूजर्स का कहना है कि पोर्टल आराम से खुल रहा है और AIS को कुछ ही सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है. वहीं, कुछ यूजर्स के लिए AIS डाउनलोड होने में 10 मिनट तक का समय लगा रहा है.

पॉलिसी प्रीमियम भरने में देरी पड़ेगी भारी

नई दिल्ली। सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST हटाने का लिया है. अगले 22 सितंबर से इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. पहले इन पर 18 परसेंट की रेट से जीएसटी लगता था, लेकिन अब नए नियम के तहत लोग बिना जीएसटी पॉलिसी खरीद सकेंगे. अब कन्फ्यूजन इसी बात का है. चूंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट का लाभ 22 सितंबर से मिलने वाला है इसलिए लोगों को लग रहा है इस तारीख के बाद या इस दिन प्रीमियम जमा करने से जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है.

अगर पॉलिसी की रिनुअल तारीख 22 सितंबर से पहले है, तो आपको पेमेंट बिना किसी दुविधा के कर देना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे. आप नो-क्लेम बोनस, रिनुअल डिस्काउंट जैसे कई लाभों से वंचित रह सकते हैं।

साप्ताहिक शहर सत्ता

विधायक निधि से खर्च करने में खुशवंत, सोनी, मूणत मोतीलाल अव्वल, पुरंदर, इंद्रकुमार, अनुज पिछड़े

जिले में 5 माह में 288 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए की अनुशंसा, इसमें 4 करोड़ के 83 कार्यों को मंजूरी

रायपुर। रायपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधायक निधि के तहत विधायकों ने अभी तक 13 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 288 कार्यों को मंजूरी दिलाने के लिए अनुशंसा की है, जिनमें से 4 करोड़ 1 लाख रुपए की कुल लागत के 83 कार्यों को ही योजना एवं सांख्यिकी विभाग से मंजूरी मिल पाई है। वहीं शेष 205 कार्यों को मंजूरी की प्रक्रिया पर कार्यवाही जारी है। इधर वित्तीय वर्ष के 5 माह गुजर चुके हैं तथा 6वां महीना प्रगति पर है। इस तरह लगभग आधा साल गुजरने को है. लेकिन सातों विधानसभा क्षेत्र में से गुरु खुशवंत साहेब एवं सुनील सोनी ही दो ऐसे विधायक हैं, जिनके द्वारा विधायक फंड की 50 प्रतिशत से ज्यादा राशि के कार्यों को मंजूरी दिलाने अनुशंसा की है। हालांकि इन दोनों विधायकों की अनुशंसा पर बहुत कम राशि के कार्यों को मंजूरी मिल पाई है। राजेश मूणत एवं मोतीलाल साहू का भी फंड खर्च करने में प्रदर्शन अच्छा है। वहीं पुरंदर मिश्रा, इंदकुमार साहू एवं अनुज शर्मा खर्च करने में बहुत पीछे हैं।

सालाना 4 करोड़ मिलता है विधायक निधि फंड

विधायक निधि के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 4 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार जारी करती है। इस फंड को विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता हित से जुड़े विकास कार्यों पर खर्च करते हैं। इस राशि से मूलभूत सुविधा सड़क, पानी, नाली, बिजली, स्कूल मरम्मत, अतिरिक्त भवन, सामुदायिक भवन सहित अन्य कई तरह के जनहित से संबंधित कार्यों को स्वीकृति दी जाती है। विधायकों की स्वीकृति के बाद इन कार्यों के प्रस्ताव बनाकर योजना एवं सांख्यिकी विभाग को भेजा जाता है, जिस पर अंतिम मुहर लगाई जाती है।

कौन से विधायक ने कितने कार्य-राशि की अनुशंसा की, कितने की मिली स्वीकृति

विधायक	अनुशंसा कार्य-राशि	स्वीकृत कार्य-राशि
मोतीलाल साहू	16-1 करोड़ 37 लाख	8-63 लाख 70 हजार
राजेश मूणत	45-1 करोड़ 14 लाख	44-70 लाख
पुरंदर मिश्रा	4-23 लाख	1-5 लाख
सुनील सोनी	44-2 करोड़ 66 लाख	8-56 लाख
इंद्रकुमार साहू	7-35 लाख	7-35 लाख
अनुज शर्मा	11-69 लाख	1-10 लाख
गुरु खुशवंत साहेब	32-2 करोड़ 93 लाख	1-10 लाख

प्रभारी निधि से स्वीकृत कार्य-राशि

इन सातों विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी निधि से भी कई कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 70 लाख रुपए की लागत से 8 कार्य तथा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 90 लाख रुपए की लागत से 9 कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

भाजपा में सब चौकीदार, तो कांग्रेस में सब चमचे : पाण्डेय

रायपुर। सांसद व भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संतोष पाण्डेय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ता एक सेवक की तरह होता है जो हर परिस्थिति में देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और देश को लगातार विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते, सभी नेता होते हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अंतर्कलह से जूझती रहती है। श्री पांडेय ने आगे कहा कि भाजपा में सब कार्यकर्ता चौकीदार हैं तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता चमचे हैं। कांग्रेस के नेता कभी अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहकर संबोधित करते हैं तो कोई चमचा कहकर बताकर कांग्रेस पार्टी को चमचों की पार्टी का नाम देता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए चमचा शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का शोषण होता है इसलिए आज कांग्रेस की सभाओं में कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर नहीं आती।

बिजली बिल हाफ योजना को बंद करना जनता से धोखाः महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 20 पैसे की की कीमतों बढ़ोतरी ने आम में बढ़ोतरी जनता के साथ-साथ राज्य के वापस ले किसानों की भी कमर तोड़ दी है। घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र को इस वृद्धि से सीधे प्रभावित किया है। राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर इससे गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, यह वृद्धि तब हुई है, जब छत्तीसगढ़ कोयला और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हम न केवल अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि इन संसाधनों की आपूर्ति दूसरे को भी करते हैं। से में बिजली की मूल्य वृद्धि का कोई ठोस कारण नहीं दिखता, महंगाई के इस दौर में आम जनता आर्थिक बोझ से परेशान है। उन्होंने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 'बिजली बिल हाफ योजना' को बंद करने से जनता पर आर्थिक बोझ की दोहरी मार पड़ी है।

आम उपभोक्ताओं और उद्योगों पर प्रभाव

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि ने घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है और छोटे व्यवसायों की लागत कई गुना बढ़ गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। अप्रत्याशित वृद्धि से आम नागरिकों में भारी असंतोष है. क्योंकि उनके दैनिक जीवन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर बिजली पर निर्भर हैं। बिजली की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि कर रही है।

ये हैं प्रमुख मांगें उन्होंने कहा, सरकार बढ़ी हुई

बिजली दरों को तुरंत वापस ले। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करे। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करे। राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी वृद्धि को रोका जा सके।

डॉ. रमन बोले- अध्यक्ष लोकतंत्र के प्रहरी, उनकी निष्पक्षता, विवेक और दृढ़ता से बढ़ता है विश्वास

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, अध्यक्ष लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उनकी निष्पक्षता, विवेक और दृढ़ता ही वह शक्ति है, जो संवाद और चर्चा को जीवंत रखती है और जनता के विश्वास को मजबूत बनाती है।

11 से 13 सितम्बर, तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित (सीपीए) राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन में "संवाद और चर्चा-जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सम्मेलन में कहा, संसद और विधान सभाएं किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ होती हैं। वे सिर्फ कानून बनाने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा मंच है, जहां जनता के विश्वास और आकांक्षाओं को आकार दिया जाता है। विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है, जब विधायी संस्थाओं में खुले मन से संवाद और तर्कपूर्ण चर्चा हो। संसद जो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच होना चाहिए था, कई बार केवल राजनीतिक टकराव और शोरगुल से न केवल गंभीर मुद्दे अनुसुने रह जाते हैं, बल्कि जनता के विश्वास पर भी आघात पहुंचता है। डॉ. रमन ने कहा, सदन में तकनीकी विषयों जैसे ऊर्जा संकट, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहन चर्चा का अभाव भी दिखाई देता है।

विधानसभा बहस का अखाड़ा नहीं समाधान का केन्द्र

उन्होंने कहा, विधायी संस्थाओं में होने वाली बहसें केवल वाद-विवाद नहीं होती, बल्कि वे राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाली बौद्धिक कसरत होती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कानून और नीतियां केवल एक वर्ग या समूह के हितों को ध्यान में रखकर न बनें, बल्कि वे समाज के सभी वर्गों की जरूरतों और चिंताओं को प्रतिबिंबित करें। उन्होंने कहा, विधायी संस्थाएं केवल बहस का अखाड़ा नहीं हैं, बल्कि वे समस्याओं को सुलझाने का केन्द्र भी हैं। जब किसान, युवा एवं महिलाओं के मुद्दे विधायी मंच पर चर्चा का विषय बनते हैं, तो इनसे सरकार को दिशा मिलती है कि किन क्षेत्रों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और कौन से समाधान सबसे उपयुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा संवाद में है और जब संवाद कमजोर होता है, तो लोकतंत्र की साख भी डगमगाने लगती है।

बैज बस्तर के विकास के लिए ब्रिज नहीं, बैरियर : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर के विकास के लिए ब्रिज नहीं बैरियर हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ का विकास कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी विकास की पक्षधर नहीं रही है। श्री पांडेय ने शनिवार को एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम अविभाजित मध्यप्रदेश से संकल्पशील रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जब बस्तर के प्रभारी मंत्री थे, तब उन्होंने बस्तर के विकास को लेकर शिला रखी थी, लेकिन उन पत्थरों को किसने उखाड़ा, बस्तर की जनता भलीभांति जानती है। श्री पांडेय ने कहा, जब देश में जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्वयं बस्तर आए थे और कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी।

भूपेश को पाटन सदन का संपत्ति कर जमा करने नोटिस

पौने 2 साल पहले ही खाली कर दिया है पाटन सदन

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुराने पाटन सदन का संपत्ति कर जमा करने के लिए नोटिस जारी किया। इस नोटिस को श्री बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स में शेयर करते हुए लिखा है-मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 7258 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को उन्होंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णुदेव साय सरकार ने उन्हें नोटिस भेजा है। बताया है कि उन्हें 7258 रुपए का भुगतान करना है। भले ही यह नोटिस अवैध हो, फिर भी वह मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करेंगे। श्री भूपेश ने लिखा है अच्छा है कि वे भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी सरकार कुनकुरी सदन का भी तो टैक्स मांगेगी।

कोई नोटिस जारी नहीं हुआ : मीनल

रायपुर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यह एक ऑनलाईन जनरेटेट डिमांड है, जो प्रॉपर्टी आईडी में दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2025 तक सदन का भुगतान चूंकि श्री बघेल के नाम से हुआ है, यह संपत्तिकर नहीं है, बल्कि यूजर चार्ज, समेकित कर और जलकर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी शासकीय भवन में संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है। तकनीकी रूप से वर्तमान में यह नाम बदल जाना चाहिए था, जो नहीं बदला और अपडेट भी नहीं हुआ है। इसलिए उनके नाम से दिखाई दे रहा है। इसमें जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा।

बैज का आरोप- 8 सालों तक जीएसटी के नाम पर जनता को लूटा, अब एहसान जता रहे

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, 2017 से मोदी सरकार ने अतार्किक और मनमाना जीएसटी लगाकर देश की जनता को 8 वर्षों तक लूटा है। अब उसमें कटौती करके 8 वर्षों तक जनता की जेब पर डाले गये डाके के पाप से सरकार बच नहीं सकती। कांग्रेस ने जीएसटी की बेतहाशा दरों का उसकी समय विरोध किया था। तब मोदी सरकार अपने अहंकार में कटौती करने को तैयार नहीं थी। दवाइयों, आटा, दूध, पनीर, घी एवं खाद्य सामग्री पर 8 सालों तक भारी भरकम जीएसटी वसूल कर जनता का खून चूसने वाले अब एहसान जता रहे है। एक मध्य आय वाले का परिवार जो सालाना 3 से साढ़े तीन लाख खर्च करता था, उससे मोदी सरकार ने 8 सालों तक हर साल 50 हजार रुपए से अधिक जीएसटी के रूप में वसूला है।

जशपुर में सामुदायिक पर्यटन की नई पहल

पांच ग्रामों में होम-स्टे की शुरुआत, स्थानीय संस्कृति को मिलेगा नया आयाम

रायपुर/जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में सामुदायिक पर्यटन की एक नई पहल की शुरुआत की है। रविवार को मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय से जिले के पाँच ग्राम—देओबोरा, केरे, दनगरी, छिछली और घोघरा में होम-स्टे योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

पर्यटन को मिलेगा नया स्वरूप

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। होम-स्टे नीति से पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति, परंपराएँ, खान-पान और जीवन शैली को लेकर देश-विदेश में गहरी जिज्ञासा है। होम-स्टे के माध्यम से पर्यटक सीधे गाँवों में रहकर ग्रामीण जीवन, पूजा-पद्धति और स्थानीय परंपराओं को नजदीक से जान सकेंगे। "यह पहल जशपुर को पर्यटन नक्शे पर नई पहचान दिलाएगी और स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी," मुख्यमंत्री ने कहा।

प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र वितरण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन पर्यटन मित्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जिन्होंने सामुदायिक पर्यटन और होम-स्टे प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित युवाओं की मदद से इन गाँवों को आने वाले समय में इको-टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकेगा। विधायक रायमुनी भगत ने कहा कि जशपुर का मकरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक है और इसके साथ जिले के अनेक झरने इसे पर्यटन की दृष्टि से अनोखा बनाते हैं। विधायक गोमती साय ने कहा कि जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है और यहाँ आने वाले पर्यटक जीवनभर इस जगह की यादें संजोए रखते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।

औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का नया केंद्र बन रहा बस्तर

रायपुर। बस्तर आज विकास की स्वर्णिम सुबह का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जो क्षेत्र कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझता था, वह अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। यहाँ हर क्षेत्र,उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन में समावेशी विकास की गूंज सुनाई दे रही है। यह बदलाव न केवल बस्तर की तस्वीर बदल रहा है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की गाथा लिख रहा है। बस्तर के विकास को गति देने के लिए सरकार ने ₹5,200 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें रावघाट–जगदलपुर नई रेल लाइन (₹3,513.11 करोड़) और केके रेल लाइन (कोत्तवलसा–किरंदुल) के दोहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। ये परियोजनाएँ न केवल बस्तर में यात्रा, पर्यटन और व्यापार को नई दिशा देंगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार और औद्योगिक अवसर भी सृजित करेंगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास और मजबूत होंगे तथा बस्तर विश्वसनीय निवेश और समावेशी विकास का केंद्र बनकर उभरेगा। इसके साथ ही, बस्तर में ₹2300 करोड़ की सड़क विकास परियोजनाएँ भी स्वीकृत की गई हैं।

युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले कोरबा के 4 शिक्षक निलंबित

रायपुर। कोरबा जिले में युक्तियुक्तकरण के बाद निर्धारित विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं करने पर 4 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कई शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 माह का वेतन रोका गया है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में असंतुष्ट शिक्षकों के आवेदनों की सुनवाई जिला एवं संभाग स्तरीय समितियों में की गई।

कई अभ्यावेदन अमान्य पाए जाने के बावजूद शिक्षकों ने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके चलते संबंधित शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कोरबा जिले में प्राथमिक शालाओं के 292 सहायक शिक्षक व 15 प्रधान पाठक तथा माध्यमिक शालाओं के 153 शिक्षक व प्रधान पाठक को अतिशेष घोषित किया गया था। इन शिक्षकों को एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक-विहीन विद्यालयों में पदस्थ करने हेतु ओपन काउंसलिंग कर पदस्थापना आदेश जारी किए गए। असंतुष्ट शिक्षकों ने जिला स्तरीय समिति और बाद में उच्च न्यायालय तथा संभाग स्तरीय समिति में भी अपील की, जिनमें से कुछ को मान्य किया गया जबकि अधिकांश आवेदनों को अमान्य कर दिया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी शिक्षकों को शीघ्र ही आबंटित विद्यालयों में उपस्थिति देकर नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, वहीं जिन विद्यालयों में अब भी कमी है, वहां जिला खनिज न्यास मद से मानदेय शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

छग सरकार का बड़ा निर्णय: शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की है। वित्त विभाग से मिली अनुमति के बाद अब इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

भर्ती हेतु स्वीकृत पद

सहायक प्राध्यापक – 625 पद

क्रीड़ा अधिकारी – 25 पद

ग्रंथपाल – 50 पद

शिक्षा और युवाओं को मिलेगा लाभ

इन भर्तियों से महाविद्यालयों में शिक्षण-अध्यापन और शोध कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी, खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पुस्तकालयों का संचालन और मजबूत होगा। साथ ही, यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कदम महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने बताया कि शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए वित्त विभाग ने इस भर्ती की अनुमति दी है। इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भविष्य की पीढ़ी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी।

सरकार की सतत भर्ती पहल

पिछले 21 महीनों में राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, आदिम जाति विकास और अन्य विभागों में भी विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिक्षकों के 5000 पदों सहित अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी जारी है।

प्रदेश में अब तक 999.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 999.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में बस्तर जिले में सर्वाधिक 1402.4 मि.मी. और बेमेतरा जिले में न्यूनतम 485.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। रायपुर संभाग में रायपुर में 860.6 मि.मी., बलौदाबाजार में 723.7 मि.मी., गरियाबंद में 866.9 मि.मी., महासमुंद में 717.4 मि.मी. और धमतरी में 892.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर में 1032.0 मि.मी., मुंगेली में 1010.9 मि.मी., रायगढ़ में 1212.8 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 829.4 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1181.9 मि.मी., सक्ती में 1083.5 मि.मी., कोरबा में 1019.4 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 953.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। दुर्ग संभाग में दुर्ग में 782.0 मि.मी., कबीरधाम में 727.2 मि.मी., राजनांदगांव में 851.1 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कुपोषण उन्मूलन और आंगनबाड़ी संचालन पर कड़े निर्देश

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ली विभागीय समीक्षा बैठक

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बलरामपुर जिले के संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख निर्देश

- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाया जाए।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए।
- बाल विवाह रोकथाम के लिए किशोरी बालिकाओं को जागरूक किया जाए ताकि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।
- आंगनबाड़ी केंद्र नियमित खुलें, बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार की गुणवत्ता, साफ-सफाई और रेडी-टू-ईट वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- एनआरसी सेंटरों का संचालन सुचारू रहे और कुपोषित बच्चों को नियमित आहार उपलब्ध कराया जाए।
- प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं।
- विभाग में रिक्त पदों की भर्ती पारदर्शी ढंग से की जाए और केंद्रों की मॉनिटरिंग नियमित हो।
- सक्षम योजना से महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जाए तथा घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जनजागरूकता बढ़ाई जाए।

अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा

बैठक में महतारी वंदन योजना, चाइल्डलाइन, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सखी वन स्टॉप सेंटर सहित विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं पर चर्चा करते हुए पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए।

अनुष्का शेट्टी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

मुंबई। साउथ की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज़ फिल्म 'घाटी' को लेकर सुर्खियों में हैं। यह फिल्म 5 सितम्बर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दर्शक और समीक्षक दोनों ही अनुष्का की दमदार अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच अनुष्का शेट्टी ने अपने प्रशंसकों को चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा की है। इस खबर ने उनके चाहने वालों को निराश कर दिया है।

अनुष्का ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोट साझा करते हुए लिखा – "नीली रोशनी को मोमबत्ती की रोशनी में बदल रही हूं। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहूंगी। बस दुनिया से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही हूं। स्क्रॉलिंग के अलावा उस जीवन में लौटना चाहती हूं, जहां से हम सबने शुरुआत की थी।"

फैंस की प्रतिक्रिया

अनुष्का शेट्टी का यह पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई प्रशंसकों ने उनकी भलाई की कामना की और जल्द वापसी की उम्मीद जताई। वहीं कुछ प्रशंसक निराश भी दिखे कि अपनी पसंदीदा अभिनेत्री से जुड़ी अपडेट्स अब कुछ समय तक नहीं मिलेंगी।

फिल्मों में व्यस्त कार्यक्रम

अनुष्का शेट्टी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री हैं और 'बाहुबली' जैसी सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने खास पहचान बनाई है। उनकी हालिया फिल्म 'घाटी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। माना जा रहा है कि वे जल्द ही अपनी आने वाली परियोजनाओं की तैयारी में भी व्यस्त होंगी।

'वायुपुत्र' होगी चंदू मुंडेटी की आगामी उडी एनिमेशन फिल्म

निर्देशक चंदू मुंडेटी की नई उडी एनिमेशन फिल्म का नाम 'वायुपुत्र' है। यह फिल्म दशहरा 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म को लेकर सेलेब्स और फैंस ने चंदू को शुभकामनाएं दी हैं। चंदू ने सोशल मीडिया पर 'वायुपुत्र' का पहला पोस्टर साझा किया और इसे अपने बचपन का सपना बताया है। साथ ही उन्होंने भगवान राम, हनुमान, ऋषि वाल्मीकि और अपने परिवार को धन्यवाद दिया। इस पोस्टर में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान की तस्वीर साफ नजर आ रही है। वह पीठ घुमाए खड़े हैं और पूरा दृश्य आग की लपटों की वजह से और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा है। पोस्टर में हनुमान को एक पहाड़ पर खड़े दिखाया गया है, जो लंका को जलते देख रहे हैं। इस पोस्ट के साथ चंदू ने कैप्शन में लिखा, 'वायुपुत्र सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक पवित्र तमाशा। इस कहानी को बताने के लिए तैयार, हमारे इतिहास की आत्मा, हमारे इतिहास के पन्ने एक बचपन का सपना। भगवान श्रीराम, भगवान हनुमान, ऋषि वाल्मीकि, मेरे परिवार का धन्यवाद, गरु का धन्यवाद। जयश्रीराम। जयहनुमान।'

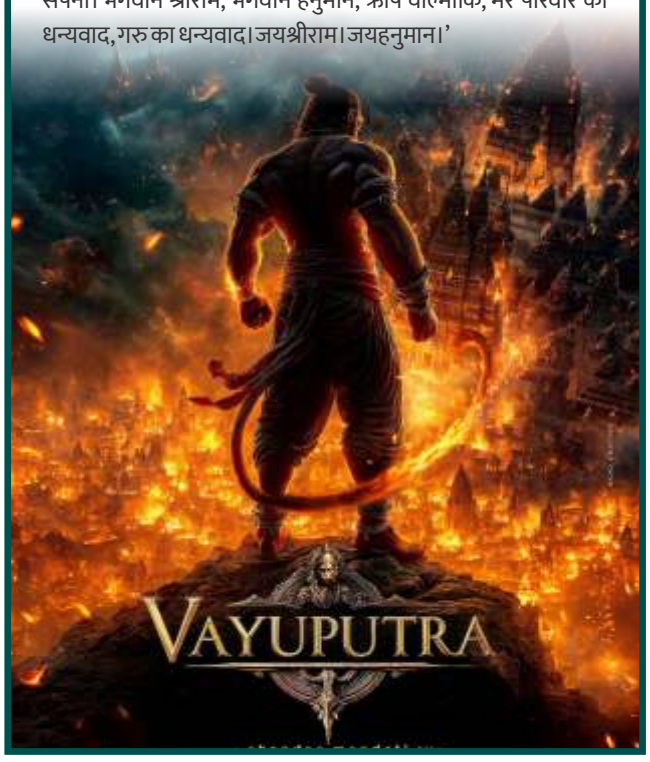

अक्षरा का जबरदस्त डांस वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले – "फायर है"

भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अक्षरा कोरियोग्राफर के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। उनका यह किलर अंदाज फैंस के बीच खूब पसंद किया जा रहा है।

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह बीटीएस (Behind The Scenes) वीडियो शेयर किया है। ब्लैक शाइनिंग ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं अक्षरा, कोरियोग्राफर एमके गुप्ता जॉय के डांस स्टेप्स फॉलो करती दिखाई दे रही हैं। डांस रिहर्सल के आखिर में अक्षरा का क्यूट अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में उन्होंने कोरियोग्राफर की ओर इशारा करते हुए अपना डांस स्टेप खत्म किया, जो दर्शकों को खूब भा रहा है।

इस शानदार डांस वीडियो के साथ अक्षरा ने कैप्शन लिखा – "रिहर्सल मोड BTS सुपर टेलेंटेड एमके गुप्ता जॉय।" अक्षरा के इस वीडियो पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं। एक फैन ने लिखा – "सुपर शेरनी।" एक और ने कहा – "बहुत अच्छा गाना है अक्षरा जी।"

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में उर्वशी को ईडी का समन

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को रविवार को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है. अभिनेत्री को 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का आदेश जारी किया गया है. यहां एक-एक कर जानिए डिटेल्स. अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने 'वनएक्सबेट' नाम की एक सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन किया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है. उसी के आधार पर उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. उनके साथ ही पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में समन भेजा गया है, उन्हें 15 सितंबर को मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है. दरअसल, ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं. इन्हीं में से एक है 'वनएक्सबेट जिसके विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार में कई सेलेब्रिटी जुड़े पाए गए हैं. जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है. इसी सिलसिले में ईडी इस ऐप का प्रचार करने वाले सभी सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रही है. ईडी ने पिछले सप्ताह भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी. इन प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर छद्म विज्ञापनों के लिए और उपयोगकर्ताओं से धन इकट्ठा करने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था.

हॉलीवुड छोड़ने के बाद 'स्ट्रेंजर थिंग्स' पर बोले डेकर- "अब इसे एक फैन की तरह देखूंगा"

नेटफ्लिक्स की मच टॉक्ड अबाउट वेब सीरीज़ स्ट्रेंजर थिंग्स अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है और दुनिया भर के फैंस की तरह अब इस शो के पूर्व एक्टर डेकर मोंटगोमरी भी इसके आखिरी सीज़न को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। सीरीज़ के दूसरे और तीसरे सीज़न में बिली हार्ग्रोव का किरदार निभा चुके डेकर अब इस शो को एक दर्शक के रूप में देखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अब ऑस्ट्रेलिया में सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। शो से थोड़ा अलग-थलग महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम सीज़न को लेकर उनकी एक्साइटमेंट कम नहीं है। 30 साल के मोंटगोमरी ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने लंबे समय से स्ट्रेंजर थिंग्स से दूरी बनाई हुई है, लेकिन अब वो एक फैन के तौर पर इसका मज़ा लेने वाले हैं। उन्होंने कहा, "अब मैं बस एक दर्शक की तरह शो देखूंगा और इस बात से मुझे बहुत खुशी है।" कोविड-19 के दौर में इंडस्ट्री से थोड़ा अलग हो जाने के बाद डेकर अब केवल कुछ चुनिंदा कलाकारों से ही संपर्क में हैं।

फवाद और वाणी की 'अबीर गुलाल' भारत में रिलीज़ को लेकर नया मोड़

- **दुनियाभर में रिलीज़ हो चुकी फिल्म, भारत में तारीख को लेकर संशय बरकरार**

मुंबई। अभिनेता फवाद खान और अभिनेत्री वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' पर पिछले दिनों खूब विवाद हुआ था। विवाद की वजह थी कि फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की मौजूदगी। इसी कारण फिल्म की भारत में रिलीज़ लगातार टलती रही।

फिल्म को दुनियाभर में 12 सितम्बर 2025 को रिलीज़ किया गया। इस दौरान भारत में इसे रिलीज़ करने को लेकर अटकलें चलती रहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फिल्म 26 सितम्बर 2025 को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के निर्माता इंडियन स्टोरीज लिमिटेड ने भारत में रिलीज़ की योजना बनाई थी। हालाँकि, इस बीच प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने साफ किया है कि भारत में फिल्म की स्क्रीनिंग की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि भारत में रिलीज़ को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है।

विवाद की पृष्ठभूमि

फिल्म की रिलीज़ को लेकर विवाद तब और गहरा गया जब जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठीं कि पाकिस्तान के कलाकारों की फिल्म भारत में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि पहले यह फिल्म मई 2025 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन टल गई।

राज्योत्सव में आसमान से बरसेंगे फूल

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनाया जा रहा यह राज्योत्सव न केवल राज्य की विकास यात्रा का उत्सव है, बल्कि यह देशभक्ति, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक भी है। इस बार वायु सेना की भागीदारी से राज्योत्सव का गौरव कई गुना बढ़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को रायपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम गढ़ेगी रोमांच और गर्व का नया इतिहास। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष में आयोजित होने वाले राज्योत्सव पर भारतीय वायु सेना का शौर्य प्रदर्शन होगा। शौर्य प्रदर्शन में वायु सेना के हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेंगे। जो आसमान से पुष्प वर्षा भी करेंगे।

क्या है सूर्यकिरण एरोबेटिक ?

सूर्यकिरण एरोबेटिक की टीम अपने सटीक और रोमांचक हवाई प्रदर्शन के लिए विश्वप्रसिद्ध है। 8 हॉक जेट विमानों से लैस यह टीम आकाश में त्रिशूल, पंखुड़ी, हार्ट शेप और राष्ट्रीय ध्वज जैसे अद्भुत आकाशीय चित्रों का निर्माण कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते है। साथ ही वायु सेना के विशेष हेलीकॉप्टर भी इस प्रदर्शन में भाग लेंगे, जो छत्तीसगढ़ के गौरवमयी अवसर को और भव्य बनाएंगे।

- भारतीय वायु सेना करेगी शौर्य प्रदर्शन
- सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का करतब
- एक दिन पूर्व पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी
- सीएम और स्पीकर ने किया था आग्रह

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती यानि 25वें स्थापना वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव 2025 में भारतीय वायु सेना का अद्भुत शौर्य प्रदर्शन राज्यवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह पहला अवसर होगा जब राज्योत्सव के मंच से वायु सेना की प्रतिष्ठित सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में रंग-बिरंगे करतब दिखाएगी। इस वर्ष छत्तीसगढ़ गठन को 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और छत्तीसगढ में रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। समारोह में शामिल होने का न्योता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने श्री मोदी को दिया था। श्री मोदी ने उसे स्वीकार कर लिया है।

राज्योत्सव में वायु सेना के शौर्य प्रदर्शन को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में विमानन विभाग एवं भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए तकनीकी और लॉजिस्टिक तैयारियों की जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय और समयबद्ध तैयारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। विभागों पर आयोजन की रूपरेखा, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, दर्शक प्रबंधन और प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी है।

एसीएस सुब्रत बोले- "छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में इस बार राज्य के नागरिकों को देश की वायु शक्ति का जीवंत प्रदर्शन देखने का एक दुर्लभ अवसर मिलेगा, जिसे हर स्तर पर सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए हमारी तैयारियां और सभी विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित हैं। राजधानी के आसमान में सूर्यकिरण एरोबेटिक की टीम अपने करतब से प्रदेशवासियों को रोमांचित करेंगी। यह जनमानस के लिए यादगार आयोजन होगा।"

तैयारियों में जुटा विभाग

- लोक निर्माण विभाग
- परिवहन विभाग
- संस्कृति विभाग
- जनसंपर्क विभाग
- गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग
- रायपुर जिला प्रशासन

एक दिन पहले आएंगे पीएम

छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए इस एक नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे। इस बार का राज्योत्सव रजत जयंती वाला होगा। इसको यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने खास तैयारी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनको इसकी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ आने का आग्रह किया था। श्री मोदी ने खास महोत्सव में शिरकत करने पर सहमति जता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार यहां पर दो दिनों तक रहेंगे। वे 31 अक्टूबर को यहां पहुंच जाएंगे। वे यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन राजधानी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसमें सबसे अहम विधानसभा भवन का लोकार्पण है। इसके बाद शाम को वे राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे। और भी कुछ कार्यक्रम इसमें जुड़ सकते हैं।

नए विधानसभा भवन का लोकार्पण

छत्तीसगढ़ गठन के बाद विधानसभा पुराने भवन में संचालित होती रही है। अब नवा रायपुर में विधानसभा का नया भवन तैयार किया गया है। 300 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले विधानसभा भवन में तीन प्रमुख विंग बनाए गए हैं। विंग-ए में विधानसभा सचिवालय, विंग-बी में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय सहित विधानसभा सदन व सेंट्रल हॉल, तथा विंग-सी में उप मुख्यमंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों के कार्यालय होंगे। विधानसभा के बी विंग को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इंटीरियर का कार्य भी अंतिम चरण में है। विधानसभा 52 एकड़ में बना है। यह नवीन विधानसभा भवन आधुनिक तकनीकी विशेषताओं और सांस्कृतिक सौंदर्य से युक्त एक भव्य परिसर होगा। सदन में 200 विधायकों के बैठने की क्षमता के साथ-साथ 500 दर्शकों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया गया है।

नशे के बाद नंगापन... !

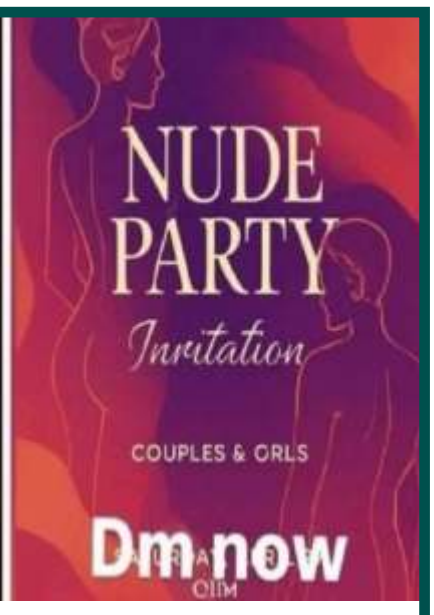

हिंदू संगठनों की नाराजगी और आयोजन का खुलासा

- एक्शन में आई रायपुर पुलिस, हायपर क्लब के 6 अरेस्ट
- न्यूड पार्टी, क्लोज पार्टी, स्ट्रेंजर्स पार्टी का बढ़ रहा क्रेज
- 40 हजार से 1 लाख रुपए तक की है पार्टी में एंट्री
- हर तरह के नशे से लेकर रूम तक का है बंदोबस्त

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस के लिए एक नई चुनौती पेश है। न्यूड, क्लोज और स्ट्रेंजर पार्टी। पहले से ही ड्रग्स, गांजा और सरेराह गुंडागर्दी-चाकूबाजी को लेकर सरकार और पुलिस कांग्रेस के निशाने में थी। अब नशे के साथ नंगेपन से लबरेज आयोजन से मामला ज्यादा संगीन हो गया है। हालांकि आयोजन होने से पहले ही रायपुर पुलिस के एक्शन से आयोजनकर्ता और इस न्यूड पार्टी में शिरकत करने की हामी भरने वाले लड़के-लड़कियां शॉर्टलिस्ट हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भाजपा पर हमलावर बनी हुई है।

पार्टी में यह इंतजाम

- **न्यूड पार्टी -** कपल एंट्री के लिए 1 लाख और सिंगल के लिए 40 हजार रूपये एंट्री फी। इसमें आयोजकों द्वारा रूम की भी व्यवस्था होती है। पार्टी में हेरोइन, एमडीएमए जैसे नशे का भी अरेजमेंट होता है।
- **क्लोज पार्टी-** इसमें केवल 18 से 20 लोगों को ही अनुमति दी जाती है। क्लोज पार्टी रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती थी। इसकी एंट्री फीस 40 हजार रुपए थी, जबकि कपल एंट्री के लिए 1 लाख रुपए वसूले जाते थे। इसमें रूम की भी व्यवस्था होती थी।
- **स्ट्रेंजर्स पार्टी -** इसमें केवल भोजन की व्यवस्था होती है। हर एक पैग के लिए अलग से कीमत देनी होती है। हुक्का की भी व्यवस्था होती है। अधिकतम 110 लोगों के शामिल होने की व्यवस्था और एंट्री फीस 2 से 5 हजार रुपए तय होती है।
- **पूल पार्टी-** स्वीमिंग पुल में नहाते-पीते और मजे लूटते है, 40 से 60 को अनुमति। सिंगल और कपल के लिए मनमाफिक एंट्री वसूली।

शहर सत्ता/रायपुर। गोवा, मुंबई और अन्य मेट्रो सिटी की तर्ज पर छतिशध की राजधानी रायपुर में भी न्यूड पार्टी की तैयारी का मामला सामने आया है। साथ ही स्ट्रेंजर पार्टी के आयोजन की चर्चा रही। इसका आयोजन अपरिचित क्लब द्वारा भाठागांव स्थित एसएस फार्म हाउस में 21 सितंबर की शाम 4 बजे से रात 3 बजे तक होने वाला था। न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर पूल पार्टी के आयोजकों पर पुलिस ने हायपर क्लब के मैनेजर जेम्स बैक, संतोष जेवानी, अजय महापात्र, एसएस गुप्ता, टीनू सिंह और देवेंद्र कुमार समेत 6 को हिरासत में लिया है।

10 दिन पहले पार्टी प्रमोशन, 21 युवा थे तैयार

अपरिचित क्लब भाठागांव स्थित फार्महाउस में 21 सितंबर की शाम 4 बजे से रात 3 बजे तक न्यूड पार्टी का आयोजन होना था। रायपुर में 'न्यूड-पार्टी' कल्चर के प्रमोटर्स ने 10 दिन पहले पार्टी का प्रमोशन शुरू किया था। पोस्टर में कहा गया कि 18 साल से ऊपर के युवक-युवती पार्टी के लिए आमंत्रित है। इसमें शामिल होने के लिए 21 युवाओं की रजामंदी भी मिल गई थी। पुलिस पता लगा रही है कि कितने और कौन लोग थे वो जो अपना रजिस्ट्रेशन पार्टी के लिए करवा रहे थे।

इंस्टाग्राम से यूजर का आईपी एड्रेस खंगाल रहे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ लाल उमेद सिंह के मुताबिक "जिस आईडी से न्यूड पार्टी का पोस्ट किया गया था, उसकी जांच की जा रही है। इंस्टाग्राम से यूजर का आईपी एड्रेस मांगा गया है। पता लगा रहे हैं कि क्या वास्तव में ऐसी पार्टी का आयोजन होना था या फिर सिर्फ अफवाह है।"

देश का कानून और संस्कृति नहीं देती अनुमति

भारत में कानूनी और सांस्कृतिक कारणों से सार्वजनिक रूप से न्यूड पार्टी की अनुमति नहीं है। यह प्रैक्टिस ज्यादातर पश्चिमी देशों या इंटरनेशनल न्यूडिस्ट कम्युनिटी तक सीमित है। हालांकि, कहीं-कहीं चोरी छिपे इस तरह के आयोजन की खबरें आती रहती है। इसमें प्रतिभागी बिना कपड़ों के पूरी तरह नग्न अवस्था में शामिल होते हैं। यूरोप और अमेरिका में न्यूडिस्ट बीचेज और रिसॉर्ट बहुत कॉमन है।

सियासी बयानबाज़ी का ऐसा छौंका

कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने कहा भाजपा शासनकाल में वायरल पोस्टर्स में शराब और ड्रग्स परोसे जाने के संकेत तो पहले ही सामने आ चुके थे, अब इसमें नग्नता का लालच देकर युवाओं को आकर्षित करने की बात भी उजागर हो रही है।

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ल बोले "पुलिस और सरकार क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ, देश के इतिहास में भी यह पहली घटना है इस प्रकार के आयोजन या तो सरकार की मर्जी से होते है या सरकार की विफलता से जब सरकार नाम की संस्था की अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब ऐसी घटनाएं होती है। यह न्यूड पार्टी भाजपा के संस्कारों की नग्नता को प्रदर्शित करता है।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा "भाजपा की सरकार है और ऐसी नग्नता भरे आयोजनकर्ताओं का सरकार और पुलिस से खौफ ख़त्म हो गया है। महानगरों का यह ट्रेंड अब राजधानी रायपुर तक पेअर पसारने लगा है। निश्चित ही यह गृहमंत्री विजय शर्मा और पुलिस की नाकामी है जो नशे के कारोबार से लेकर सरेराह गुंडागर्दी और अब नग्नता को बढ़ावा देने वालों से ऑखें मूंदें हैं।

रायपुर में स्ट्रेंजर पूल पार्टी का पर्दाफाश, 7 लोग गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी में प्रस्तावित स्ट्रेंजर पूल पार्टी से जुड़ा मामला पुलिस की कार्रवाई के बाद सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पार्टी को लेकर पुलिस ने फार्महाउस संचालक, इवेंट मैनेजर और क्लब संचालक समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पार्टी 21 सितंबर को भाठागांव स्थित एसएस फार्म हाउस में रखी गई थी। इसके प्रचार के लिए अपरिचत क्लब नाम से इंस्टाग्राम पेज और WHAT IS RAIPUR नाम से ऑनलाइन प्रमोशन किया गया। एंट्री फीस युवाओं से ऑनलाइन ट्रांसफर करवाई जा रही थी। आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर रायपुर पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। इसी टीम ने सात आरोपियों को पकड़ा। इनमें इवेंट ऑर्गेनाइजर संतोष जेवानी और अजय महापात्रा, फार्म हाउस उपलब्ध कराने वाले संतोष गुप्ता, प्रमोशन करने वाले अवनीश गंगवानी और हाइपर क्लब संचालक जेम्स बेक शामिल हैं। जेम्स बेक के साथ दीपक सिंह और देवेन्द्र कुमार यादव भी पार्टी के प्रचार में जुड़े थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ आयोजकों पर ही नहीं, बल्कि जिन व्यक्तियों ने अपने बैंक खातों से एंट्री फीस जमा कराई है, उनकी भी जांच की जाएगी। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और जांच आगे बढ़ रही है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)।